PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

मई 2022 / Issue -1

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises,
Government of India

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

WHAT IS UGC'S DUAL DEGREE PROGRAMME AND HOW WILL IT WORK?

- नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना
- स्वास्थ्य अवसंरचना से सामाजिक न्याय
- भारत में बढ़ रहा सभ्यता संकट
- भारत -ब्रिटेन सम्बन्धो के नए आयाम
- यूजीसी के द्वारा एक साथ दो डिग्री कोर्सेज की सुविधा देने के मायने
- कोविड-१९ के बाद की एमएसएमई के लिए सबक
- भारत में बिजली संकट एक गंभीर मुद्दा

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

IAS / PCS
TARGET 2023-24

PMI

(PRE+MAINS+INTERVIEW)
Programme-2022-23

Starting From
8th May 2022

FEATURES :

- Short, concise and UPSC /UPPSC trend oriented syllabus .
- Topic wise preparation.
- Research and analysis of evolving trends of questions by team of dedicated experts.
- Special attention to Prelims, Mains and Personality test.
- Comprehensive coverage of UPSC, UPPSC & other states exam syllabus within 1 year with specific publications by Government of India.
- First phase (January to June-06 months)- full foundation syllabus coverage based on NCERT of Class 6th to 10th with current affairs for targetting UPSC ,UPPSC & other examination.
- Second phase (July to December-06 months)- advance syllabus coverage based on NCERT of Class 11th & 12th with current affairs.
- Personality evaluation and feedback with every PMI exam.

Fee :
(Including GST)

☞ **For Dhyeya Students : Rs. 2,000/-**

☞ **For Other Students : Rs. 5,000/-**

This Fee is valid for 12 Months consisting 12 Tests.

9205274741 / 42

www.dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PMI SCHEDULE, 2022-23

S.No.	Month	Prelims Date (2nd Sunday of every month)	Mains Date (3rd Sunday of every month)	Interview Date
1.	May, 2022	08/05/2022	15/05/2022	Last Sunday of every month
2.	June, 2022	12/06/2022	19/06/2022	Last Sunday of every month
3.	July, 2022	10/07/2022	17/07/2022	Last Sunday of every month
4.	August, 2022	14/08/2022	21/08/2022	Last Sunday of every month
5.	September., 2022	11/09/2022	18/09/2022	Last Sunday of every month
6.	October, 2022	09/10/2022	16/10/2022	Last Sunday of every month
7.	November, 2022	13/11/2022	20/11/2022	Last Sunday of every month
8.	December, 2022	11/12/2022	18/12/2022	Last Sunday of every month
9.	January, 2023	08/01/2023	15/01/2023	Last Sunday of every month
10.	February, 2023	12/02/2023	19/02/2023	Last Sunday of every month
11.	March, 2023	12/03/2023	19/03/2023	Last Sunday of every month
12.	April, 2023	09/04/2023	16/04/2023	Last Sunday of every month

☞ These allotted dates are tentative and subject to change under special circumstances.

9205274741 / 42

www.dhyeyaias.com

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

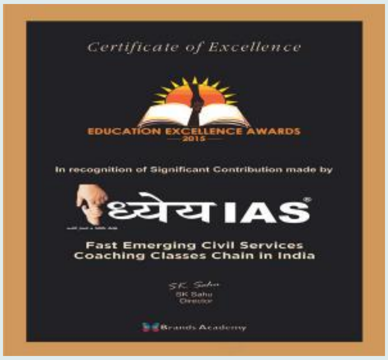

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक.ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय **IAS**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	· विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	· क्यू. एच. खान
सहसंपादक	· गौतम तिवारी
उप-संपादक	· आशुतोष मिश्र
	· सौरभ चक्रवर्ती
प्रकाशन प्रबंधक	· डॉ.एस.एम.खालिद
संपादकीय सहयोग	· प्रिंस, अमन, गौरव चौधरी, देवेंद्र सिंह, लोकेश शुक्ल
मुख्य लेखक	· विवेक ओझा
सहायक लेखक	· मृत्युंजय त्रिपाठी,
मुख्य समीक्षक	· ए.के श्रीवास्तव
	· विनीत अनुराग
	· बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	· प्रगति केसरवानी
	· पुनीष जैन
टंकण	· सचिन
	· तरून
कार्यालय सहायक	· राजू , चन्दन, अरुण

साभार : PIB, द हिंदु, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR : 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR : 9205274743
LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD : 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ) : 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR) : 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA : 9205336037, 9205336038
KANPUR : 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR : 8599071555
SRINAGAR (J&K) : 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————— 1-14

- यूजीसी के द्वारा एक साथ दो डिग्री कोर्सेज की सुविधा देने के मायने
- नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना
- स्वास्थ्य अवसंरचना से सामाजिक न्याय
- भारत -ब्रिटेन सम्बन्धो के नए आयाम
- भारत में बिजली संकट एक गंभीर मुद्दा
- COVID-19 के बाद की MSMEs के लिए सबक
- भारत में बढ़ रहा सभ्यता संकट

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ---------- 15-16
संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ---------- 16-17
संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण ---------- 18-19
संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक ---------- 19-21
संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक ---------- 22-23
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें ---------- 24-27
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ---------- 28
ब्रेन बूस्टर ---------- 29-35
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा समसामयिक बहुविकल्पीय प्रश्न ---------- 36-41
GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ---------- 42
व्यक्ति विशेष ---------- 43
इतिहास विषय की शब्दावलियां ---------- 44-45

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

यूजीसी की छात्रों को एक साथ दो डिग्री कोर्सेज की सुविधा देने के मायने

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा स्तर पर एक साथ दो नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा करने के प्रावधान के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2022- 23 से लागू होंगे। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति 2020 के इरादों के अनुरूप हैं।

पृष्ठभूमि

- नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत और लचीली होनी चाहिए। यह नीति अध्ययन के लिए विषयों के संयोजन को सक्षम करने के लिए, एक कल्पनाशील और लचीली पाठ्यचर्या संरचना के विकास को बढ़ावा देती है।
- यह नीति वर्तमान में सख्त सीमाओं को हटाने के लिए कई प्रविष्टियाँ और निकास बिंदु भी प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य आजीवन सीखने की नई संभावनाएं पैदा करना भी है। यह औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा मोड दोनों को शामिल करते हुए सीखने के लिए मार्गों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

दिशा निर्देश

- एक छात्र भौतिक मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है बशर्ते कि एक कार्यक्रम के लिए कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम के साथ ओवरलैप न हो।
- एक छात्र दो अकादमिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है, एक पूर्णकालिक शारीरिक मोड में और दूसरा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग/ऑनलाइन मोड में।
- एक छात्र एक साथ दो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग/ऑनलाइन कार्यक्रम भी पूरा कर सकता है।
- ओपन और डिस्टेंस लर्निंग/ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों को केवल ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरा करना चाहिए जो इस तरह के कार्यक्रम को चलाने के लिए यूजीसी/सांविधिक परिषद/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- ये दिशानिर्देश यूजीसी द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे। उन छात्रों द्वारा कोई पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ण किए हैं।
- विषयों का अनुमत संयोजन स्वयं संस्थानों द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न होगा।
- छात्रों द्वारा चुने गए दो कार्यक्रमों को समान स्तर पर (या तो स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर या डिप्लोमा स्तर) पर होना चाहिए।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उपस्थिति संस्थानों द्वारा स्वयं तय की जाएगी।
- प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड मौजूदा यूजीसी और विश्वविद्यालय के मानदंडों के आधार पर तय किया जाएगा।
- छात्रों को एक कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे कार्यक्रम की क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दो नियमित पाठ्यक्रम

इन नए दिशानिर्देशों का सबसे विवादास्पद पहलू एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रमों की अनुमति देना है।

पक्ष में तर्क

- यह प्रावधान नई शिक्षा नीति 2020 के इरादे के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है।
- इस प्रावधान को जारी करने से पहले लचीलेपन की कमी, अंत:विषय अनुसंधान और ज्ञान साझा करने की दिशा में आगे बढ़ने में एक बड़ी बाधा थी।
- यह छात्रों की क्षमताओं और आकां. क्षाओं के आधार पर शिक्षा को निजीकृत और अनुकूलित करेगा।
- यह प्रावधान विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगा।
- यह प्रावधान छात्रों के करियर और नौकरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा।
- यह कला और विज्ञान, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच अलगाव को दूर करेगा।
- यह सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच हानिकारक पदानुक्रम को समाप्त करेगा।
- यह प्रावधान छात्रों को विचारशील और रचनात्मक व्यक्ति बनाने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषाओं के साथ-साथ पेशेवर, तकनीकी और व्यावसा. यिक विषयों सहित कई विषयों को उपलब्ध कराएगा।
- यह प्रावधान विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उनके शैक्षिक मानकों के अनुसार अपने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता प्रदान करता है।
- यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि स्नातक, स्नातकोत्तर या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बीच कोई ओवरलैप न हो।
- एक ही समय में दो नियमित पाठ्यक्रमों की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार है।
- यह छात्रों को एक विषय से दूसरे विषय में करियर बदलने में मदद करेगा।

- इससे समय प्रबंधन कौशल का विकास भी होगा।
- इस प्रावधान से वर्षों के हिसाब से छात्रों का समय भी बचेगा।

विपक्ष में तर्क

- नई शिक्षा नीति 2020 में सीधे इस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।
- यह छात्रों के लिए अतिरिक्त मानसिक तनाव पैदा करेगा।
- यह छात्रों के लिए अधिक महंगा हो सकता है, जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
- किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना कठिन होगा।
- जॉब मार्केट में दो अलग-अलग स्ट्रीम में डिग्री होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता है।
- आमतौर पर, एक नियमित डिग्री इस तरह से डिजाइन की जाती है कि छात्रों का समग्र और सर्वांगीण विकास हो। इसलिए एक साथ दो डिग्री का उपयोग सीमित है।
- यह प्रावधान प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी पैदा कर सकता है।
- इससे आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखने वाले छात्रों द्वारा दो सीटों पर कब्जा भी किया जा सकता है।
- यह प्रावधान विभिन्न कॉलेजों में शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए परिवहन समस्या भी पैदा कर सकता है।
- आमतौर पर एक डिग्री करने में दिन का अधिकांश समय लगता है, अत: दो डिग्री करने वाला छात्र दोनों में से किसी एक के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाएगा।
- छात्रों के विविध समूह की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षाशास्त्र को भी उपयुक्त परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।
- यह प्रावधान विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए लाजिस्टिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्याएं भी पैदा करेगा।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार, भारत में राष्ट्रीय औसत कॉलेज घनत्व 30 प्रति लाख है। इन सीमित कॉलेजों को, एक छात्र के लिए दो सीटें आरक्षित करने के बजाय व्यापक आबादी की सेवा के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- यूजीसी की फुरकान कमर कमेटी ने भी एक दशक पहले इस प्रावधान के खिलाफ सिफारिश की थी।

आगे का रास्ता

- यूजीसी इंजीनियरिंग विषयों में डबल/मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए अपने 2004 के दस्तावेज द्वारा सुझाए गए सुझावों अनुसार एक साथ दो डिग्री की अनुमति देने के बजाय दूसरी डिग्री की अवधि को कम कर सकता है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल एक कार्यक्रम का चयन करने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाए।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को भौतिक मोड में दूसरी डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को केवल खाली सीटें उपलब्ध करानी चाहिए।
- यूजीसी को शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि उन्हें नए प्रावधान के अनुकूलन में मदद मिल सके।
- नए प्रावधान को लागू करने की आड़ में संस्थागत स्वायत्तता में बाधा नहीं आनी चाहिए।
- प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों को और अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा सीमित कक्षा के बुनियादी ढांचे पर बोझ डाले बिना दूसरी डिग्री की मांग पूरी हो सके।
- दूसरी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को करियर परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे उस डिग्री का चयन कर सकें जो नौकरी के बाजार में उनकी पहली डिग्री का पूरक हो और साथ ही उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार उपयुक्त हो।
- छात्रों को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जहां उन्हें प्राकृतिक लाभ है, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति लाभ दूसरी डिग्री के लिए भी जारी रहना चाहिए।

निष्कर्ष

हालांकि एक साथ दो नियमित डिग्री के फायदे और नुकसान बहस का विषय हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कदम एक अधिक जीवंत और प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा के माहौल की ओर बढ़ने में यूजीसी के संकल्प को दर्शाता है। छात्रों को नौकरी के बाजार की मांगों के लिए और अधिक तैयार करने की कोशिश करते हुए, यूजीसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च शिक्षा चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता और सेवा की भावना को विकसित करके 'सा विद्या या विमुक्तये' (शिक्षा जो स्वतंत्रता प्रदान करती है) के प्राचीन भारतीय लक्ष्य को पूरा करे।

NOTES

नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित वित्तीय परिवर्तन की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

नवीकरणीय ऊर्जा में रूपांतरण से केंद्र और राज्यों पर वित्तीय रूप से दबाव बढ़ेगा। हानिकारक उत्पादों (शराब, सिगरेट) पर अधिक कर लगाकर वैकल्पिक रूप से इसकी कुछ हद तक क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

संदर्भ :-

- भारत की नेट शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं ने जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा परिवर्तन को अपरिहार्य बना दिया है। चूंकि भारत, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। ऐसे में इस संक्रमण. कालीन परिस्थितियों में राजकोषीय प्रबन्धन की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है।

सी.ओ.पी के 26वें सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए पांच रणनीति की घोषणा की। जिसे पंचामृत कहा जाता है। इन पांच बिंदुओं में शामिल हैं :-

- भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट प्राप्त कर लेगा।
- भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करेगा।
- भारत अब से 2030 तक, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।
- 2030 तक, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करेगा वहीं, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
- हाल ही में प्रकाशित आईएमएफ-बीयू वर्किंग पेपर में एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है कि कैसे अगले दो दशकों में सरकारों (केंद्र और राज्य दोनों) को कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाला राजस्व प्रभावित होगा क्योंकि भारत तीव्र गति से अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। विकास, कीमत और करों पर मानक मान्यताओं के तहत, 2040 तक जीवाश्म ईंधन से राजस्व में निरंतर वृद्धि होगी। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और समग्र सरकारी बजट के हिस्से के रूप में राजस्व में तीव्र गि. रावट आएगी। जिससे अगले दो दशकों में केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए राजकोषीय चुनौतियां उत्पन्न होगी।
- जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व का विश्लेषण करने पर, पाया गया कि 2019 तक केंद्र के राजस्व का पांचवां हिस्सा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता था, जिसमें कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) और गैर-कर राजस्व (रॉयल्टी, लाभांश आदि सहित) दोनों शामिल थे।
- राज्य सरकारों के लिए, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त राजस्व, कुल राजस्व के 8 प्रतिशत से कम था। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए संयुक्त राजस्व, कुल एकत्र किए गए राजस्व का 13 प्रतिशत था, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% है। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व, भारत के रक्षा व्यय से बहुत अधिक है और केंद्र और राज्यों दोनों के संयुक्त शिक्षा, संस्कृति और खेल व्यय के बराबर है।
- जैसे ही भारत अपनी नेट-शून्य प्रतिबद्धताओं का पालन करना शुरू करेगा, सबसे पहले उसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना होगा। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का एक प्रमुख स्रोत गायब हो जाएगा। जैसे-जैसे भारत इस ऊर्जा संक्रमण से गुजरेगा है, उसे राजकोषीय संक्रमण से गुजरना होगा।

राजकोषीय संक्रमण :-

भारत राजकोषीय संक्रमण से कैसे निपटेगा ?

- सरकार कोयले या कार्बन जैसी किसी अन्य वस्तु पर अतिरिक्त कर लगा सकती है। जैसे कोरोना काल जैसी राजस्व की तनावपूर्ण स्थिति में, सरकारों ने ऊर्जा को राजस्व बढाने का सबसे अच्छा स्रोत माना था।
- 2019 में, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकलता है कि कोविड की अवधि के दौरान, सरकार की राजस्व के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के कारण, पेट्रो उत्पादों की कीमतों में वृद्धि देखी गई।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद, भारत में पेट्रो उत्पाद पर कर वृद्धि के कारण, कीमतों में कमी नहीं आई। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोलियम से प्राप्त राजस्व 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत था जो कि उच्च उत्पाद शुल्क और वैट के कारण 2020-21 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत हो गया।
- इस तरह के अप्रत्यक्ष उपायों से, एक सीमित अवधि के लिए जीवाश्म ईंधन से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। समय के साथ जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले राज. स्व में निरंतर गिरावट आएगी क्योंकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में रूपांतरित हो जाएग. ा। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आएगी।
- अनुमान के मुताबिक यदि मौजूदा आर्थिक रुझान जारी रहता है तो राजस्व में, 2019 के सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% से घटकर 2030 में 1.8% और 2040 में घटकर 1% तक रहने का अनुमान है।
- केंद्र और राज्यों पर राजकोषीय दबाव ऊर्जा अवसंरचना में निवेश को कठिन बना देगा।

जिसके कारण, ऊर्जा संक्रमण के एक बड़े हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से ईवी पर उत्पाद शुल्क की रियायत, जीएसटी में छूट, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत दी गई रियायतें आदि राज्यों के वित्तीय तनाव में वृद्धि करेगी। सब्सिडी में कटौती से या प्रोत्साहन की कमी से, ऊर्जा संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

- घटते राजस्व का राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यह राज्य सरकारों को दिए गए जीएसटी मुआवजे का अंतिम वर्ष है, जो कुछ राज्यों के राजस्व पर दबाव डाल सकता है। इसके अलावा, जीएसटी संरचना के तहत, राज्यों के पास कर बढ़ाने के लिए सीमित स्वायत्तता है, जो इस मुद्दे को भड़काने में एक अहम कारक बन सकता है।
- केंद्र ने पिछले कुछ वर्षों में उपकर के माध्यम से अधिक राजस्व एकत्र करना शुरू कर दिया है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है।
- सवाल यह उठता है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपट सकता है? भारत में कर-जीडीपी अनुपात पिछले एक दशक से लगभग समान रहा है, लेकिन वर्तमान समय में, जीएसटी राजस्व में अब वृद्धि हो रही है।

जलवायु वित्तपोषण के लिए समाधान :-

- **जलवायु परिवर्तन से निपटने में बैंकों की भूमिका :-** एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में, संक्रमण के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र भारत की वाणिज्यिक गतिविधियों की रीढ़ रहा है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में, एक प्रमुख चालक के रूप में, इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों के लिए देश में हरित बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में निरंतर प्रयासों के माध्यम से नेट शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता मिली है।
- **हरित वित्तपोषण:-** भारत का समर्पित "हरित वित्त" क्षेत्र आज भी प्रारंभिक अवस्था में है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (सीपी.आई) द्वारा जारी एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत वर्ष 2018 में 160 बिलियन डॉलर की वार्षिक आवश्यकता की तुलना में, जलवायु निवेश में केवल 18 बिलियन डॉलर ही एकत्रित कर पाया है।
- **ग्रीन बॉन्ड:-** निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां जो कम कॉर्बन उत्सर्जन वाली हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण का मुख्य स्रोत हैं, भारत में हरित पहल के लिए वित्त पोषण का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है।

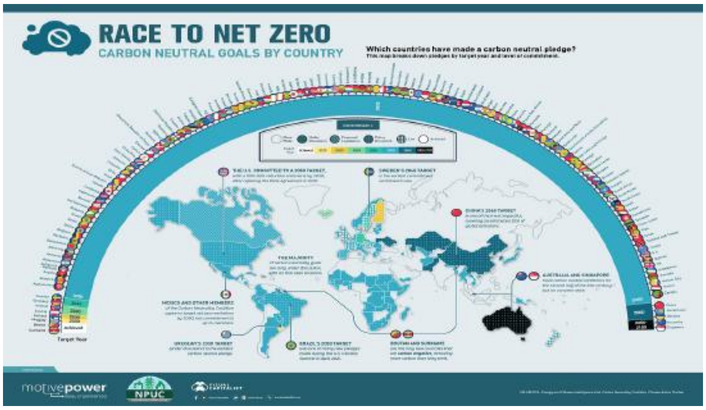

आगे की राह :-

- भारत दीर्घकाल में, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व की भरपाई अन्य स्रोतों से कर सकता है। इसके लिए सरकार को कर आधार में वृद्धि के लिए औपचारिक अभियान जारी रखने होंगे। हालांकि, ये लंबी अवधि की प्रक्रियाएं हैं। अल्पावधि में, भारत को जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा में कमी की भरपाई के लिए किसी अन्य स्रोत से राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता होगी जैसे शराब, तंबाकू आदि से निर्मित वस्तुओं पर कर वृद्धि द्वारा।

NOTES

स्वास्थ्य अवसंरचना से सामाजिक न्याय की प्राप्ति

सन्दर्भ

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से न सिर्फ बीमारी का निदान होता है बल्कि सामाजिक न्याय की भी स्थापना होती है।

परिचय

हाल ही में भुज में एक मल्टी स्पेसियाल्टी हॉस्पिटल के उद्घाटन (वर्चुअली) करने के उपरान्त भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक न्याय की प्राप्ति में महत्वपूर्ण साधन बताया है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं गरीबी उन्मूलन के साथ जुडी होती हैं इसके साथ ही वे सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य नीतिया, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं।

भारत में स्वास्थ्य की स्थिति

भारत एक बड़ी जनसँख्या वाला विकासशील देश है। यहाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी बु. नियादी सुविधाएं अभी विकास की अवस्था में हैं जिनके सम्मुख प्राय: चुनौतियाँ आती रहती हैं। हाल ही में आये महामारी (कोरोना) ने भारत के स्वास्थ्य प्रणाली की कमियों को भी उजागिर किया। यदयपि इतनी बड़ी जनसँख्या तथा बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना के अभाव में भी भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्रक ने बेहतर प्रदर्शन किया परन्तु कोरोना जैसी समस्या हेतु यह पर्याप्त नहीं था। इसके साथ ही साथ भारत में पारम्परिक रूप से ह्रदयघात, मधुमेह, कुष्ठ रोग जैसी कई समस्याएं पाई जाती हैं जो न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं बल्कि उनके मध्य असमानता बढ़ाकर सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय को जन्म देती हैं। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्रक के सम्मुख बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव है।

भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना के सम्मुख चुनौतियां

- वर्तमान समय में सम्पूर्ण भारत में 80,312 एमबीबीएस सीटों की सम्मिलित क्षमता वाले 541 मेडिकल कॉलेज हैं। यह निसंदेह एक बड़ी संख्या है परन्तु भारत जैसे विशाल देश जहाँ प्रतिवर्ष भारी संख्या में मरीज निकलते हैं वहां यह संख्या अपर्याप्त है। देश में 13000 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि वैश्विक स्तर पर आदर्श अनुपात 1:1000 है। यह एक बड़ी चुनौती है।
- अधिकांश द्वितीयक तथा तृतीयक केयर हॉस्पिटल्स टियर-1 तथा टियर-2 शहरा. ें में स्थित हैं। इसके साथ ही साथ अति विशेष्ज्ञ डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में असमानता आती है जो आगे चलकर राज्यवार असमानता में परिणत होती है। केरल, तामिलनाडु तथा दिल्ली जैसे राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए हैं वहीं बिहार, झारखण्ड तथा उत्तरपूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं।
- 2017 की एक विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर 85.7 चिकित्सक (पाकिस्तान में 98, श्रीलंका में 100 और जापान में 241) हैं। भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर मात्र 53 बेड ही उपलब्ध है जबकि पाकिस्तान में 63, बांग्लादेश में 79.5, और जापान में 1,298 हैं।
- इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर 172.7 नर्स और दाई की उपलब्धता है जबकि जापान में 1,220 हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का 62% ओओपी है जिसके कारण भारत में अधिक आउट-ऑफ-पॉकेट (ओओपी) व्यय सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक है।
- भारत में स्वास्थ्य व्यय में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है जबकि शेष 20 प्रतिशत का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र भारत में 58 प्रतिशत अस्पतालों और 81 प्रतिशत डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। चुकि निजी क्षेत्रक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं अत: या तो ये गरीब की पहुंच से बाहर होते हैं अथवा इनका व्यय वहन करने के उपरांत वह व्यक्ति आर्थिक रूप से पंगु हो जाता है जिससे सामाजिक -आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है।
- इसके साथ साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी पढाई का महंगा होना, कर्मियों में स्किल की कमी, रिमोट क्षेत्रों में उपयुक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मशीनों की कमी इत्यादि कई अन्य समस्याएं हैं जो भारत के स्वास्थ्य अवसंरचना को कमजोर करती हैं।

स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने हेतु किये गए प्रयास

हाल के वर्षो में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के कई प्रयास किये गए हैं जिनका वर्णन निम्नवत है –

भारत का स्वास्थ्य बजट

- सामान्य रूप से भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी के 1.3% से 1.5 प्रतिशत तक रहता था। हालाँकि कोरोना काल के प्रभाव को कम करने हेतु वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 2,23,846 करोड़ रुपए 'स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र' पर व्यय के लिये आवंटित किये गए थे। यह कुल बजट प्रावधान का लगभग 6.43% था।।
- इस वर्ष (बजट वर्ष 2022-23) में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु 89, 251 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है। 2025 तक भारत का लक्ष्य

स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी के 2.5% तक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। जो कि स्वास्थ्य नीति में वर्णित लक्ष्य की तरफ प्रगति को दिखा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति :-

- 2017 में आई इस नीति के व्यापक सिद्धांतो में व्यावसायिकता, अखंडता और नैतिकता, इक्विटी, सामर्थ्य, सार्वभौमिकता, रोगी केंद्रित और देखभाल की गुणवत्ता, जवाबदेही और बहुलवाद सम्मिलित हैं।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य वित्तीय कठिनाई के बिना गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। यह नीति चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने की बात करती है।

स्वास्थ्य अवसंरचना हेतु निवेश

- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन को पांच वर्षों की अवधि में ₹64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। यह योजना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 12 केंद्रीय संस्थानों तथा 602 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना तक प्रावधान करता है।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना योजना देश के दुर्गम क्षेत्रो में चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा वितरण में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है। इस वर्ष इस योजना हेतु 10000 करोंड का बजटीय आवंटन किया गया है।
- इन योजनाओ के साथ साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, आयुषमान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कोरोना वैक्सीनेशन, इत्यादि योजनाओ में निवेश के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है जो सामाजिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- कोरोना काल के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा एशियन डेवेलोपमेंट बैंक ने संयुक्त रूप से भारत को वैक्सीनेशन के लिए 2 बिलियन डालर का ऋण प्रदान किया। इसके साथ ही विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य अवसंरचना से किस प्रकार सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है –

- सामाजिक अवसंरचना में वृद्धि से गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगी। बेहतर मानव संसाधन हेतु बेहतर स्वास्थ्य आवश्यक है। बेहतर स्वास्थ्य से मनुष्य की उत्पादकता बढ़ती है अतः बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना के सहयोग पर आधारित मानव संसाधन देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अपनी जीवन स्थिति में भी सुधार करेगा जिससे "न्याय" की प्राप्ति होगी।
- स्वास्थ्य सेवाओं में महिला बल (डाक्टर, दाई, नर्स) की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अतः स्वास्थ्य अवसंरचना में वृद्धि से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी जो लैंगिक समानता के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक होगा।
- जहाँ भी अस्पताल अथवा अन्य स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनेंगे वहां आस- पास अप्रत्यक्ष रोजगार (चाय, परिवहन, मेडिकल स्टोर) उत्पन्न होगा जो आर्थिक विकास के द्वारा सामाजिक न्याय में सहायक होगा।
- गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलती है। गरीबो के स्वास्थ्य व्यय को सरकार द्वारा वहन किये जाने से न सिर्फ गरीब अपने धन को अन्य उपयोगी गतिविधियों में लगा सकता है बल्कि सरकार के प्रति उसके विश्वास में भी वृद्धि होती है।अतः विवश होकर किये गए अराजक कार्य (चोरी, डकैती, लूट) में भी कमी आती है। अन्यत्र यह स्थिति सामाजिक न्याय की अवस्था की तरफ बढ़ाती है।

निष्कर्ष

सामाजिक न्याय की अवधारणा सामाजिक समानता तथा सामाजिक अधिकारों से सम्बंधित है। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आधार (लैंगिक, जातिगत, धार्मिक इत्यादि) पर मानव द्वारा मानव के शोषण को समाप्त करना है। सामाजिक न्याय का महत्व इतना अधिक है कि इसे सामाजिक – राजनैतिक दार्शनिक इसे साध्य मूल्य मानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को संविधान के एक उद्देश्य के रूप में वर्णित किया गया है तथा संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्वों) में इसे प्रभावी ढंग से रखा गया है। देश में प्रभावी स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा जो कि देश में सामाजिक न्याय के आदर्श को प्राप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य अवसंरचना सामाजिक न्याय के साध्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण साधन है।

NOTES

भारत -ब्रिटेन सम्बन्धो के नए आयाम

सन्दर्भ

हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा भारत की यात्रा की गई। ध्यातव्य हो कि इसके कुछ समय पूर्व ब्रिटिश विदेश सचिव मिस ट्रस ने भारत की यात्रा की थी। रूस-यूक्रेन युद्ध के मध्य इन दोनों ही उच्च स्तरीय यात्राओं ने भारत तथा ब्रिटेन के सम्बन्धो को नवीन आयाम प्रदान किया है।

परिचय

रूस- यूक्रेन युद्ध द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बीच भारत तथा ब्रिटेन के सम्बन्ध नवीन आयामों को छू रहे हैं। इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन की विदेश सचिव भारत के साथ हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (मई 2021) को अंतिम रूप देने के लिए आई तदोपरांत ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की यात्रा की गई। ध्यातव्य हो कि इस युद्ध के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद में वृद्धि हुई है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह दौरा उस बढे हुए कद का सूचक है। इस दौरान भारत न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कद को मजबूती प्रदान कर रहा है बल्कि द्विपक्षीय सम्बन्धो को भी मजबूत कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह प्रथम भारत यात्रा थी (ध्यातव्य हो कि इसके पूर्व की यात्रा कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई थी) जिसका आरम्भ उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गाँधी को श्रद्धा-सुमन अर्पित करके किया। इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर मुहर लगी जिनमे मुक्त व्यापार समझौता, समग्र रणनैतिक समझौता, साइबर सुरक्षा पर समझौता इत्यादि मुख्य रहे।

भारत तथा ब्रिटेन के मध्य सहयोग के नए आयाम:

- **कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप:-** इस सम्मलेन के दौरान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (मई 2021) को अंतिम रूप दिया गया इसके साथ ही साथ 2030 तक में भारत -ब्रिटेन सम्बन्धो के द्विपक्षीय विकास पर समझौते की बात की गई।
- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र:-** ब्रिटेन ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत तथा ब्रिटेन के मजबूत रिश्तो की वकालत की है तथा यह कहा है कि द्विपक्षीय सम्बन्ध न सिर्फ आर्थिक सम्पन्नता लाएंगे बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा भी मजबूत करेंगे। इस क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने भारत के हिन्द-प्रशांत समुद्री पहल (इंडो-पैसिफिक ओसियन इनिसिएटिव) का भाग बनना स्वीकार किया है इसके साथ ही साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री सुरक्षा में भागीदार बनने का वादा किया है।

o ध्यातव्य हो कि 2021 में भारत, ब्रिटेन, मलेसिया, थाईलैंड, सिंगापुर के मध्य बंगाल की खाड़ी में संयुक्त जलसेना अभ्यास किया गया था।

- **साइबर सुरक्षा प्रोग्राम:-** ब्रिटेन ने साइबर सुरक्षा तथा रक्षा व्यापार पर आपसी समझौते को बढ़ावा देने की बात की है। इस दौरान एक नवीन साइबर सुरक्षा प्रोग्राम की घोषणा की गई है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारत में ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा दोनों देशो के मध्य साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास की रूपरेखा तैयार करना है।
- **स्ट्रैटेजिक टेक डायलॉग:-** इस यात्रा के दौरान भारत तथा ब्रिटेन ने पहली स्ट्रैटेजिक टेक डायलॉग की घोषणा की है जो नवाचारी तकनीकों पर एक मंत्रिस्तरीय वार्ता होगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा:-** ब्रिटेन ने भारत में नवीकर. .णीय ऊर्जा स्रोतों के लिए 70 मिलियन पाउंड के निवेश की घोषणा की है।
- **मुक्त व्यापार:-** भारत तथा ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर वार्ता की गई है। ध्यातव्य हो कि भारत तथा ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहल आगे बढ़ गए है। इस सन्दर्भ में 26 नीतिगत क्षेत्रो पर बात की जाएगी।
- **निवेश**

o भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश कंप. नियों से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान में निवेश करने का आग्रह किया गया है।

o भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्लोबल इन्नोवेशन पार्टनरशिप भारत के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण पहल साबित होगी। इसके तहत थर्ड वर्ल्ड देशों में "मेड इन इण्डिया" को बढ़ावा देने के लिए भारत और ब्रिटेन 100 मिलियन डॉलर तक का संयुक्त निवेश करेंगे। जिससे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति होगी तथा जलवायु परिवर्तन के शमन में सहायता मिलेगी।

- **अन्य विन्दु**

o ब्रिटेन ने भारत के "आत्मनिर्भर भारत " योजना की सराहना की है। इसके साथ ही दोनों देश ग्लास्गो की प्रतिबद्धताओं के प्रति सहमत हुए हैं तथा इस सन्दर्भ में भारत ने ब्रिटेन को नेशनल हाइड्रोजन मिशन में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया है।

o इसके साथ ही साथ भारत तथा ब्रिटेन ने यूक्रेन युद्ध के समापन, शांत तथा स्थिर अफगानिस्तान, क्षेत्रीय अखंडता तथा आतंकवाद के विरोध के सम्बन्ध में भी वार्ता की गई।

नये सम्बन्धों के समक्ष चुनौतियाँ

यद्यपि वर्तमान समय में भारत तथा ब्रिटेन के मध्य चुनौतियां नगण्य हैं परन्तु ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पूर्व यात्रा पर आई ब्रिटिश सचिव ने रूस के साथ भारत के सम्बन्धो पर चिंता व्यक्त की थी। ध्यातव्य हो कि भारत रूस के साथ रुपया - रुबेल में तेल का व्यापार कर रहा है। ब्रिटिश सचिव ने इस सन्दर्भ में रूस

की आक्रमकता को रोकने के लिए भारत से अपील की थी परन्तु भारत का यह तर्क है कि भारत से अधिक तेल यूरोप खरीद रहा है अत: भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रुपया -रुबेल में व्यापार जारी रखेगा।

भारत के लिए ब्रिटेन का महत्व

- ब्रिटेन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति है। ब्रिटेन की नौसेना की पहुंच ओमान, सिंगापुर, केन्या, बहरीन तथा ब्रिटिश इंडियन ओसियन क्षेत्र में है। वर्तमान समय में विश्व शक्ति संतुलन अटलांटिक से हटकर एशिया -प्रशांत क्षेत्र में पहुंच रहा है जहाँ चीन की आक्रामकता पहले से ही विद्यमान है। अत: इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने में भारत- ब्रिटेन सहयोग महत्वपूर्ण है।
- ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षापरिषद का स्थायी सदस्य है। वर्तमान समय में चीन के अतिरिक्त अन्य सभी स्थायी देशो के साथ भारत के सम्बन्ध है अत: इस स्थिति में ब्रिटेन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षापरिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने में सहायता कर सकता है।
- हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएसए में परमाणु पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ है। संभावित रूप से भारत के साथ भी इस प्रकार के समझौते किये जा सकते हैं जो भारत की रक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा में सहायक होगा।
- भारत अक्सर विकसित देशों से पर्यावरण के सन्दर्भ में वित्त तथा तकनीक हस्तांतरण की आग्रह करता है। भारत ब्रिटेन से इस सन्दर्भ में बात-चीत कर विकासशील देशो का नेतृत्वकर्ता बन सकता है।
- वर्तमान समय में भारत बहुपक्षीय व्यापार के स्थान पर द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर ध्यान दे रहा है। ब्रिटेन इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है।

ब्रिटेन के लिए भारत का महत्व

- ब्रेक्सिट के उपरान्त ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की तलाश है जो भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते से पूर्ण हो सकती है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटेन एक वैश्विक शक्ति था जो अब क्षेत्रीय शक्ति में बदल चूका है। ब्रिटेन पुन: "वैश्विक ब्रिटेन (ग्लोबल ब्रिटेन)" बनना चाह रहा है जिसके लिए उसे भारत के सहयोग की आवश्यकता है।

- भारत विश्व का सर्वाधिक युवा तथा बड़ा बाजार है। भारत की क्रय क्षमता लगातार बढ़ रही है यहाँ तक कि क्रय क्षमता के आधार पर यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अत: भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तथा निर्यात के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध होगा।
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन वैश्विक स्तर पर भारत के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं इसके साथ ही रूस -यूक्रेन युद्ध को शांत करने में सभी देश भारत की भूमिका चाह रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन भारत के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहता है।
- भारत हिन्द- प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है तथा वर्तमान में शक्तिसंतुलन इस क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ब्रिटेन एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाना चाह रहा है अत: वह भारत से सहयोग का आकांक्षी है।

दोनों देशो के सम्बन्ध में चुनौतियाँ

- ब्रिटेन ने सदियों तक भारत को उपनिवेश बनाया था तथा आज भी ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों पर हमले होते हैं। इन स्थितियों में भारत तथा ब्रिटेन के मध्य पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में चुनौतियाँ व्याप्त है।
- वर्तमान समय में वैश्वीकरण अपने संभावित अंत की तरफ बढ़ रहा है ऐसे में मुक्त व्यापार तथा बहुपक्षीय व्यापार के समक्ष चुनौतियाँ आएँगी।
- रूस-यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देश रूस का विरोध कर रहे हैं जबकि भारत निष्पक्षता की नीति पर चल रहा है।
- पर्यावरण के मुद्दों, तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार के मुद्दों पर दोनों देशो के मध्य तनाव बना रहा है।

निष्कर्ष

भारत ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस "सार्थक यात्रा" से आशान्वित है। वहीं ब्रिटेन भी भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ सम्बन्धो को मजबूत करने की इच्छा रखता है। ब्रेक्सिट के बाद भारत का सहयोग ब्रिटेन को मजबूत कर सकता है वहीँ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता बनने में ब्रिटेन भारत का सहयोग कर सकता है। इस प्रकार दोनों देश एक दुसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि वर्तमान समय की स्थितियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है ऐसे में ब्रिटेन भारत के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है।

NOTES

भारत का बिजली संकट गंभीर मामला क्यों

चर्चा में क्यों ?

उच्च कोयला उत्पादन के बावजूद, भारत में थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं।

संदर्भ :-

देश भर के कई राज्यों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह ऐसा घटनाक्रम है जो आने वाले हफ्तों में बिजली की कमी की ओर ले जाएगा है क्योंकि भारत में अप्रैल से अक्टूबर तक बिजली की मांग में वृद्धि होती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि उच्च वैश्विक तापीय कोयले की कीमतें और सामान्य से कम आयात संकट को और बढ़ा देगा।

वास्तव में, कोयले की आपूर्ति की कमी ऐसे समय में चल रही है जब बिजली की मांग बढ़ रही है और जुलाई 2022 में 200 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से अधिक की बिजली की मांग को पार करने की उम्मीद है। वित्तवर्ष 2022 के लिए दैनिक पीक बिजली की मांग औसतन 187 गीगावाट **(GW)** है। 1 से 12 अप्रैल के दौरान, औसत दैनिक पीक डिमांड 194 गीगावाट से अधिक थी।

बाजारों में कीमतें भी कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर हैं। भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) में बाजार समाशोधन मूल्य (एमसीपी) लगभग 4.4 रुपये प्रति किलोवाट-घंटे (केडब्ल्यूएच) था, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है।

- कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 55% हिस्सा पूरा करता है। देश की औद्योगिक वि. रासत स्वदेशी कोयले पर बनी थी।
- आज भारत के पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार है।
- चीन के बाद भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

भारत के लिए कोयला क्यों आवश्यक है?

- कोयला भारत में सबसे आवश्यक और प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 55% हिस्सा पूरा करता है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सी. मित भंडार क्षमता, जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरण-संरक्षण प्रतिबंध और परमाणु ऊर्जा की भू-राजनीतिक धारणा के साथ, कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य में महत्तवपूर्ण स्थान रखता है।
- वर्तमान में, भारत के पास निकट भविष्य में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा का संभावित प्रतिस्थापन नहीं है।

कोयले की मांग-आपूर्ति के बेमेल होने के क्या कारण हैं?

1. बिजली की बढ़ती मांग :-

उदाहरण के लिए, हाल ही में, नई दिल्ली में बिजली की सर्वाधिक मांग 5,460 मेग. ावाट (मेगावाट) तक पहुंच गई, जो अप्रैल के पहले पखवाड़े में अब तक की सबसे अधिक मांग है। राष्ट्रीय राजधानी की सर्वोच्च बिजली की मांग 2021 या पिछले वर्ष में इस आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी। बिजली की बढ़ती मांग के कारण आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्य बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। जबकि बिजली उत्पादन कंपनियों के पास कोयला स्टॉक बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

2. स्टॉक में कोयले की उपलब्धता का अभाव :-

आम तौर पर, एक बिजली संयंत्र को 26 दिनों के कोयले का स्टॉक बनाए रखना चाहिए। हालांकि, वर्तमान में, कई बिजली संयंत्र कोयले के कम भंडार की रेपोर्टिंग कर रहे हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के डेटा से पता चलता है कि 173 में से 97 बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडारण निम्न स्तर पर है। सामान्य परिदृश्य की तुलना में इनके पास औसतन 28% स्टॉक है।

3. खराब लॉजिस्टिक सुविधाएं :-

कोयले के परिवहन के लिए रेलवे रेक का न होना भी एक बड़ी समस्या है।

राज्य की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) भी बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया नहीं चुका पाई हैं। कोविड-19 महामारी ने अब कई राज्यों के वित्त को कमजोर कर दिया है, जिससे राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम कंपनियों के बकाया चुकाने की क्षमता पर संदेह पैदा हो गया है।

4. कोयले की कमी के अन्य कारक :-

वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2016 में बंपर उत्पादन के बाद भी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा उत्पादन में ठहराव रहा। पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने केंद्र और गैर-भारतीय जनता पार्टी के कोयला समृद्ध राज्यों के बीच टकराव की ओर इशारा किया है, जिससे पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण की मंजूरी में देरी हो सकती है। डिस्कॉम का उच्च बकाया और सीआईएल को भुगतान करने वाली जेनकोस द्वारा देरी ने परिदृश्य को जटिल बना दिया है।

क्या आप भारत में कोयला भंडार के बारे में जानते हैं?

- 27 प्रमुख कोयला क्षेत्रों में फैले कोयले के भंडार मुख्य रूप से देश के पूर्वी और दक्षिण-मध्य भागों तक ही सीमित हैं।
- भारत के कोयला संसाधन प्रायद्वीपीय भारत के पुराने गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध हैं।

- लिग्नाइट का भंडार लगभग 36 बिलियन टन के स्तर पर है, जिसमें से 90% दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में है।
- भारत में कुल कोयला भंडार के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: झारखंड > ओडिशा > छत्तीसगढ़> पश्चिम बंगाल> मध्य प्रदेश।

इस संकट का कारण क्या है?

- भारत के विद्युत क्षेत्र का मुख्य आधार कोयले की आपूर्ति में कमी के परिणामस्वरूप ताप विद्युत संयंत्रों में यह संकट उत्पन्न हुआ है।
- कोयला आधारित बिजली उत्पादन, कुल 396 गीगावाट में से लगभग 210 गीगावाट (GW) की क्षमता के साथ, मार्च 2022 तक भारत की कुल बिजली क्षमता का लगभग 53 प्रतिशत है।
- विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति कम होने से बिजली की कटौती होगी। ऐसा ही परिदृश्य सितंबर-अक्टूबर 2021 में सामने आया था। कोयले की अधिक मांग और आपूर्ति में रुकावट (मुख्य रूप से भारी बारिश के कारण) के कारण, बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक में तेजी से गिरावट आई। सरकार के ठोस प्रयासों से, स्टॉक उस स्तर तक बढ़ गया जो औसतन 10 दिनों के लिए प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के 85 प्रतिशत या सीधे शब्दों में कहें तो क्षमता के लिए पर्याप्त है।

कोयले की कमी कितनी गंभीर है?

ताप विद्युत संयंत्रों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। नेशनल पावर पोर्टल के अनुसार, 13 अप्रैल तक 11 आयातित कोयला-आधारित (आईसीबी) बिजली संयंत्रों के पास महत्वपूर्ण स्टॉक ही शेष थे। इसी तरह, 79 घरेलू कोयला-आधारित बिजली संयंत्र प्रमुख कमोडिटी के महत्वपूर्ण स्टॉक की कमी का सामना कर रहे थे। 13 अप्रैल को कुल 173 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से, कुल उपलब्ध स्टॉक 2.76 मीट्रिक टन की दैनिक आवश्यकता के मुकाबले 23.17 मिलियन टन (एमटी) था। इस स्तर पर स्टॉक नौ दिनों से भी कम समय तक चलेगा।

यह संकट हर साल क्यों आता है?

- भारत में बिजली संयंत्रों में कोयले की कम आपूर्ति होना कोई नई बात नहीं है। कमी लगभग हर साल होती है और सरकार अपने विभिन्न उपायों के बावजूद इस समस्या पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाई है।
- इस मुद्दे के केंद्र में इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न मंत्रालयों - बिजली मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेलवे के बीच योजना और समन्वय की कमी है।
- जबकि कोयला मंत्रालय पर्याप्त रेकों की अनुपलब्धता के लिए भारतीय रेलवे को दोषी ठहराता है, रेलवे ने कोल इंडिया (सीआईएल) द्वारा रेकों की लोडिंग और अनलोडिंग में कुप्रबंधन की ओर इशारा किया है।
- सीआईएल और अन्य पीएसयू खनिकों द्वारा उच्च कोयला उत्पादन और प्रेषण के बावजूद, पिछले छह महीनों में बिजली संयंत्रों में आपूर्ति अभी भी 15 दिनों से अधिक नहीं हुई है और इसके लिए समन्वय और योजना की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के कदम :-

- सबसे पहले, सरकार ने संशोधित कोयला भंडारण मानदंड जारी किए हैं, जो बिजली संयंत्रों को हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए अनिवार्य करते हैं।
- इसके अलावा, बिजली, कोयला, रेलवे, सीईए, सीआईएल और एससीसीएल मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह नियमित रूप से बैठक करता है ताकि ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न परिचालन निर्णय लिए जा सकें।
- विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार बनाने की दृष्टि से 2022-23 के दौरान सम्मिश्रण के लिए बिजली संयंत्रों को लगभग 36 मीट्रिक टन कोयले का आयात करने की सलाह दी है। थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) में कोयले के स्टॉक की निगरानी

सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के पास एक कोर मैनेजमेंट टीम (सीएमटी) भी है और टीपीपी को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सीएमटी में परिचालन निर्णय लिए जा रहे हैं।

आगे की राह :-

- जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में तापमान के चरम पर पहुंचने की संभावना के साथ, अगले दो से चार महीनों में बिजली की मांग में और तेजी आएगी।
- घटते कोयले के स्टॉक को देखते हुए, ग्रिड मई और अगस्त के बीच अधिक भार के कारण आपूर्ति देने में सक्षम नहीं हो पता है, जिससे असामान्य रूप से गर्मी के मौसम में किसी भी समय लोड-शेडिंग और अन्य बिजली कटौती कमोबेश अपरिहार्य हो जाती है। इस परिदृश्य में, सरकार को भारत के राज्यों में बिजली संकट से निपटने के लिए कदम उठाने होंगे।

NOTES

COVID-19 के बाद की दुनिया में MSMEs के लिए सबक

चर्चा में क्यों ?

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (**MSMEs**) **COVID-19** से प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे और तब से ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तराखंड में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 90% छोटी फर्मों के कारोबार में गिरावट आई थी।

मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्यम (MSMEs)- परिभाषा

विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से संबंधित **MSMEs** को निवेश और टर्नओवर के मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है।

- मध्यम उद्यम- संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश: 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार: 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।
- लघु उद्यम- संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश: 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।
- सूक्ष्म उद्यम- संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश: 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार: 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।

MSMEs की विशेषताएँ

MSMEs आमतौर पर एकमात्र व्यापारी, साझेदारी या छोटी कंपनी द्वारा एकल व्यावसायिक प्रतिष्ठान से चलाए जाते हैं। उनके पास सीमित भौगोलिक वितरण, उत्पाद श्रेणी और बाजार हिस्सेदारी है। उनका ग्राहक आधार छोटा है और व्यापार के विफल होने की संभावना बहुत अधिक है। बड़ी फर्मों की तुलना में उनके पास आनुपातिक रूप से उच्च अनुपालन लागत का बोझ है। उनके पास सीमित नियामक और बाजार संबंधी जानकारी है। तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों तक उनकी पहुंच भी कम है और उनकी प्रशिक्षण क्षमताएं सीमित हैं।

भारत में MSMEs का महत्व

आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए **MSMEs** महत्वपूर्ण हैं। वे औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करते हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने में भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारत में पारंपरिक कारीगर उद्योगों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में भी भूमिका निभाता है।

भारत में MSMEs के पिछड़ेपन के कारण

भारतीय अर्थव्यवस्था में **MSME** क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, निम्नलिखित कारणों से उनकी स्थिति अभी भी पिछड़ी हुई है

- **MSMEs**, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों के लिए बुनियादी ढांचे की बाधाएं हैं। वे औपचारिकता, प्रौद्योगिकी अपनाने, क्षमता निर्माण, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आदि जैसी आवश्यक समर्थन प्रणालियों से अपर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं। यह स्थिति उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- ऋण और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच सीमित है। उचित लागत पर फंड उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं लेकिन हाल की अवधि में उनकी साख का आकलन करने में कठिनाई के साथ-साथ अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थता के कारण उन्हें ऋण वितरण धीमा रहा है।
- उन्हें अक्सर देरी से भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे उनके नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता प्रभावित होती है। ऐसी प्राप्तियों की प्राप्ति में देरी से उनके परिचालन चक्र में वृद्धि होती है और नए ऑर्डर प्राप्त करने या मौजूदा ऑर्डर को पूरा करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।

COVID-19 महामारी के दौरान MSMEs **द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं**

COVID-19 महामारी के दौरान, MSMEs को सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के कारण आर्थिक गतिविधियों और गतिशीलता पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। जनता और फर्मों के पास सीमित पूंजी उपलब्धता के कारण उन्हें मांग में कमी का भी सामना करना पड़ा। कच्चे माल की कमी और व्यापार पर प्रतिबंध भी थे। भुगतान में देरी और श्रम की कमी ने भी उनके कार्य चक्र को प्रभावित किया।

रिकवरी में बाधाएं

आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान के बाद भी, **MSMEs** अभी भी व्यावसायिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। ये अनिश्चितताएं उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता का लाभ उठाने में संकोचित करती हैं। **COVID-19** अवधि के दौरान प्रवास के कारण कुशल श्रमिकों की सीमित आपूर्ति भी है। कच्चे माल से संबंधित मुद्रास्फीति के कारण उनकी उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है। विलंबित भुगतान, कम मांग और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान का पुराना मुद्दा अभी भी उन्हें

प्रभावित कर रहा है।

MSMEs के लिए सबक

कुछ फर्में COVID-19 महामारी के दौरान अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाने में सफल रहीं। वे अन्य फर्मों के लिए सबक प्रदान करती हैं।

सबसे पहले, मानव स्वास्थ्य गतिविधियों, फार्मास्युटिकल, औषधीय, रासायनिक और वनस्पति उत्पादों के निर्माण, खाद्य और पेय सेवाओं और परिधान के निर्माण जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाली फर्मों ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखा।

दूसरे, जिन फर्मों ने अपने ईंट और मोर्टार मॉडल के अलावा ई-कॉमर्स गतिविधियों को जल्दी से अपनाया, उन्होंने भी अपनी स्थिरता और यहां तक कि लाभप्रदता सुनिश्चित की।

तीसरा, फर्में जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को उन उत्पादों और सेवाओं की ओर मोड़ दिया जिनकी मांग थी, बढ़ी है। मास्क, सैनिटाइजर के उत्पादन और उत्पादों की होम डिलीवरी से संबंधित फर्म इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

चौथा, जिन फर्मों ने नए अवसरों को प्रदान करने वाले क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अपनी बचत की थी, उन्होंने प्रतिकूल समय में लचीलापन दिखाया। इस प्रकार, उचित वित्तीय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक था।

पांचवां, जिन फर्मों ने अपने मानव संसाधनों का उपयोग स्मार्ट तरीके से किया। उन्होंने गिग अर्थव्यवस्था के समय में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखा।

छठा, जिन फर्मों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति का विस्तार और रखरखाव किया, उन्होंने विकास दिखाया, क्योंकि COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गतिविधियों में कोई बाधा नहीं थी। इन फर्मों ने खोज इंजन अनुकूलन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया अभियान आदि जैसे व्यापार और विपणन के नए तरीकों को अपनाया।

COVID-19 के बाद MSMEs क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपाय

सरकार ने COVID-19 संघर्षों के बाद लाभदायक बनाने के लिए MSMEs को मदद करने का भी प्रयास किया है। उसने एमएसएमई के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू की हैं।

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना MSMEs को कम ब्याज पर अतिरिक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वे अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं।
- सरकार ने विशेष रूप से MSMEs क्षेत्र की स्वदेशी फर्मों की मदद के लिए 200 करोड़ तक की खरीद पर वैश्विक निविदाओं को भी अस्वीकार कर दिया है।
- सरकार ने फंड ऑफ फंड्स भी स्थापित किया है जो विकास क्षमता वाले MSMEs की जरूरत को पूरा करने के लिए इक्विटी फंडिंग प्रदान करता है।
- सरकार ने MSMEsको पुनर्वर्गीकृत किया है और इस प्रकार कुछ फर्मों को MSMEs नेट के अन्दर लाया है जो पहले इससे बाहर थीं।
- क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड योजना MSMEs मंत्रालय द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ MSMEs की मदद के लिए शुरू की गई थी। ट्रस्ट संपार्श्विक के स्थान पर उनकी ओर से क्रेडिट की गारंटी देता है।
- प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU) ने डैडम क्षेत्र से कुल वार्षिक खरीद के न्यूनतम 25% के रूप में वार्षिक खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है।
- एमएसएमई को ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की छूट का लाभ भी प्रदान किया गया है जिससे उन्हें कम लागत पर अपना लाभ बढ़ाने के लिए ऋण सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है।

आगे का रास्ता

छोटे व्यवसायों के लिए आपातकालीन निधि का प्रावधान होना चाहिए जो व्यवसाय की शुरुआत से अनिवार्य होना चाहिए। इस फंड का उपयोग अनिश्चित परिस्थितियों में छोटी फर्मों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। इस कोष में प्रत्येक फर्म के योगदान को उनके कारोबार से जोड़ा जाना चाहिए। सरकार उनके योगदान का एक अंश देकर इसे और आकर्षक बना सकती है। छोटे व्यवसायों के लिए भी एक बीमा योजना होनी चाहिए जो प्रतिकूल समय में उनकी मदद कर सके। चूंकि देश में 60 लाख से अधिक MSMEs हैं, इसलिए बीमा कंपनियों के लिए बाजार में अपार संभावनाएं हैं। सरकार MSMEs की ओर से प्रारंभिक प्रीमियम या प्रीमियम के एक अंश का भुगतान करके फर्मों को प्रोत्साहित कर सकती है।

निष्कर्ष

अगर इन सुझावों को प्रभावी ढंग से तैयार और कार्यान्वित किया जाता है, तो प्रतिकूल समय के दौरान MSMEs को मदद मिलेगी और सामान्य व्यावसायिक समय के दौरान उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

NOTES

भारत में बढ़ रहा सभ्यता संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रत्नागिरी महाराष्ट्र में छिपकली से दुष्कर्म की घटना हुई है। यह भारत में सभ्यता संकट की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

पृष्ठभूमि

सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में 4 लोगों के द्वारा बंगाल मॉनिटर लिजार्ड (छिपकली) के साथ दुष्कर्म किया गया। यह पहली घटना नहीं है इसके पूर्व केरल में एक गर्भवती हथिनी को पटाखो से भरा अन्नास खिलाया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार की घटनाएं तथाकथित "सभ्य आधुनिक शिक्षित समाज" पर एक कलंक है।

भारत में मनुष्यों और जानवरों के बीच सहजीवी संबंधों की संस्कृति

परंपरागत रूप से पशु भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उन्हें देवताओं के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे आदिवासियों के लंबे समय से साथी रहे हैं। इनका उपयोग गाँव के मेलों में मनोरंजन के लिए भी किया जाता रहा है। उन्हें युद्धों में एक लाभ के रूप में इस्तेमाल किया गया है जैसे युद्ध जीतने में हाथी महत्वपूर्ण थे। वन्यजीव पर्यटन पारंपरिक समय से लोकप्रिय रहा है।

जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के हालिया रुझानों के कारण

- इंसानों और जानवरों के बीच संबंधों का व्यवसायीकरण हो गया है। जानवरों को पैसा कमाने के साधन के रूप में देखा जाता है और जिन जानवरों में कमाई की क्षमता नहीं होती है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है।
- 'वसुधैव कुटुम्बकम' (पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है) का प्राचीन मूल्य तेजी से घट रहा है जो जानवरों और मनुष्यों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
- भारतीय नागरिकों में जीवों के प्रति दयाभाव रखने का मौलिक कर्तव्य नहीं रहा है।

यह दुर्व्यवहार भारत में बढ़ते सभ्यता संकट की ओर इशारा करता है।

भारतीय समाज में सभ्यता संकट के तत्व

आधुनिक भारतीय समाज कई कुरीतियों से ग्रस्त है जो भारत में सभ्यता संकट को जन्म दे रही हैं।

ऐतिहासिक तत्व :-

वैदिक काल के सभ्य भारतीय समाज में समय के साथ साथ कई चुनौतियाँ आईं। उत्तरवैदिक काल में जातिप्रथा का जन्म हो चुका था। सामंतवादी राजपूत युग में तंत्र विद्या के महत्व के कारण पशु-बलि तथा नर बलि (विशेष रूप से जनजातियों मे), पितृसत्ता, सतीप्रथा जैसी कुरीतियां प्रबल रूप से समाज का हिस्सा बन गईं। मुगल शासन के दौरान भारत में विविधता बढ़ी जिसने सामाजिक सत्ता संघर्ष को जन्म दिया। इन सब के फलस्वरूप भारतीय समाज का ताना बाना कमजोर हो गया तथा उसे आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके यूरोपीय शक्तियों से सांस्कृतिक पराभव का सामना करना पड़ा। यूरोपीय शक्तियों के कारण भारत में सम्प्रदायवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

मॉब लिंचिंग :-

मॉब लिंचिंग से तात्पर्य भीड़ द्वारा की गई हत्या से है। 2015 में हुई दादरी मॉब लिंचिंग से लेकर पालघर मॉब लिंचिंग (2020) तक एक लम्बी श्रृंखला है जिसमे भीड़ द्वारा मात्र संशय के कारण किसी की हत्या कर दी गई हो।

लैंगिक बिभेदन:-

आधुनिक भारत भी लैंगिक विभेदन की समस्या से पूर्णतया ग्रस्त है। आज भी दहेज प्रथा, बलात विवाह, बलात्कार,सार्वजानिक अपमान, कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी कई समस्याओं से भारतीय महिलाओं को रूबरू होना पड़ता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट-2021 में 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर है। यह आंकड़े भारतीय समाज में महिलाओं की खराब स्थिति की ओर इशारा करते हैं।

जातिगत द्वन्द :-

वर्तमान समय में भी भारत में जातिगत समस्याएं इस प्रकार हैं कि अनुसूचित वर्ग को अपने जल, जैसी आवश्यक आवश्यकताओं हेतु भी संघर्ष करना पड़ता है। यह समस्या भी आधुनिक सभ्यता हेतु एक चुनौती है।

आतंकवाद, नक्सलवाद व संगठित अपराध :-

आतंकवाद तथा संगठित अपराध में भय का शासन व भय का व्यापार किया जाता है। मुंबई हमले, पुलवामा, पठानकोट जैसे कई घाव समाज पर लगे हैं। नक्सलवाद का जन्म सामाजिक, आर्थिक असमानताओं पर होता है।

क्षेत्रवादी प्रवृत्ति :-

जिस समाज ने कभी शकों, कुषाणो, को स्वीकार किया था आज उसी समाज में टकराव का आधार क्षेत्र, भाषा व बोली बन चुके हैं। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझ कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। दक्षिणी राज्यों में उत्तरी राज्य के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जम्मू- कश्मीर, लदाख तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को विश्वास संकट का सामना करना पड़ता है, यह

न मात्र सामाजिक दृष्टिकोण से वरन राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है।

सम्प्रदायवाद :-

भारत में सम्प्रदायवाद एक मुख्य समस्या है। सम्प्रदायिकता एक प्रकार का नैतिक, मान. सिक, धार्मिक रोग है जिसका निवारण संभव नहीं दिख रहा। सम्प्रदायवाद की पराकाष्ठा के रूप में भारत ने राष्ट्र विभाजन की एक बड़ी त्रासदी देखी है। वर्तमान समय में भी दिल्ली (जहांगीरपुर), राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर मध्यप्रदेश तक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर है।

मानव पशु संघर्ष :-

समाज में रह रहे लोगों द्वारा किये गए कृत्य जैसे छिपकली से दुष्कर्म, केरल का मादा हाथी के साथ व्यवहार, जानवरो की हत्या, महज मनोरंजन हेतु किया गया शिकार, सर्कस में जानवरों का उपयोग, जलीकट्टू, ये बेजुबान जानवरों पर मानवीय अत्याचारों का प्रतीक हैं।

सभ्यता संकट के कारण :-

- भारत में सम्प्रदायवाद व जातिगत समस्याओं हेतु लम्बा उपनिवेशी शासन उत्तरदायी है जिसने भारतीय संस्कृति के तत्वों को कमजोर कर दिया है।
- सत्ता न मात्र राजनीतिक पदों बल्कि आर्थिक व सामाजिक मूल्यों हेतु भी होती है। उदाहरण स्वरुप कुछ समय पूर्व तक सवर्ण समाज के मानदंडों पर प्रभावी थे परन्तु धीरे धीरे ही सही अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोग निरंतर विकास कर रहे हैं तथा समाज पर प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे है, ऐसे स्थिति में इन दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी यही स्थिति प्रभावी होती है।
- लोकतंत्र में वोटबैंक की राजनीति आधुनिक समय में सामान्य हो गई है। राजनैतिक दल जाति, धर्म के नाम पर लोगो को अपने लाभ हेतु प्रयोग करते हैं, यह स्थिति समाज को जोड़ने नहीं वरन तोड़ने का कार्य करती है। जातिगत समस्या, सम्प्रदायवाद की

स्थिति इसी का परिणाम है।

- भारत स्वयं में एक विवधता पूर्ण देश है।वह देश जहाँ नृजातीय व धार्मिक विविधता बहुत अधिक है तथा धर्म आम जन मानस के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में विविधता कहीं न कहीं संघर्ष को बढ़ावा भी देती है।
- वास्तव में किसी भी धर्म का मूल सिद्धांत शांति होती है हिंसा नहीं। परन्तु धर्म के ठेकेदारों द्वारा की गई गलत व्याख्या के फलस्वरूप जनमानस अधिक हिंसावादी हो चुका है। यह सम्प्रदायवाद हेतु मूल कारण है।
- भारत में अभी लोकतंत्र नया हैं जिससे न ही सामंतवादी शक्तियां पूर्णतया पराभूत हुईं और न ही लोकतान्त्रिक आयामों यथा समानता, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता को बहुत बल मिला है। जिससे भारतीय समाज में तनाव उत्पन्न हुआ है, लोकतंत्र तथा सामंतवाद के मध्य यह संघर्ष भी कहीं न कहीं सभ्यता संकट हेतु उत्तरदायी है।

निष्कर्ष :-

इन चारो आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। परन्तु यह स्थिति भारत के समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ रही है। इस सभ्यता संकट का समापन अत्यंत आवश्यक है। भारत की सभ्यता ने पूर्व काल से ही उथल पुथल का दौर देखा है परन्तु वह अभी भी अपने मूल सिद्धांतो से हटी नहीं है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अग्निपूजा, जल पवित्रता, प्रकृति पूजा आज भी किसी न किसी रूप में विराजमान है। पूंजीवाद से उत्पन्न समस्याएं आत्मनिर्भर भारत योजना से समाप्त की जा सकती हैं। अतः निस्संदेह भारतीय जनता में इस सभ्यता संकट को समाप्त करने की क्षमता है। भारत इस संकट को समाप्त करके निस्संदेह विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ेगा।

NOTES

संक्षिप्त मुद्दे

राष्ट्रीय

1 आईटी नियम, 2021 के तहत कुछ यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमावली, 2021 के तहत आपात. कालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए दो अलग -अलग आदेशों के तहत सोलह (16) यूट्यूब आधारित समाचार चौनल और एक (1) फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए है।

ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट छह पाकिस्तान में स्थित है।

और दस भारत के यूट्यूब समाचार चैनल शामिल हैं, जिनके दर्शकों की कुल संख्या संख्या 68 करोड़ से अधिक है। यह देखा गया कि इन चैनलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों, देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया गया था। किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने आईटी नियम. ावली, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी।

भारत के कुछ यूट्यूब चैनलें द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में संदर्भित किया गया है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को उकसाया गया। इस तरह की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की मंशा पाई गई थी।

भारत के कई यूट्यूब चैनल समाज के विभिन्न वर्गों में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से असत्या. पित समाचार और वीडियो प्रकाशित करते थे। कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा से संबंधित झूठे दावे करके प्रवासी श्रमिकों को जोखिम में डालना और कुछ धार्मिक समुदायों के लिए खतरों का आरोप लगाते हुए मनगढ़ंत दावे आदि इसके उदा. हरण हैं। ऐसी सामग्री को देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना गया।

पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर और यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में भारत के विदेशी संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए सुनियोजित तरीके का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। इन चैनलों की सामग्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता एवं विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया।

मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों का इस्तेमाल करने के विरुद्ध चेतावनी भी दी थी। भारत सरकार प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया में भारत में एक सुरक्षित और संरक्षित सूचना का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2 मिशन अंत्योदय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा मिशन अंत्योदय के कार्यान्वयन में कुछ कमियां पाई गई हैं।

मिशन अंत्योदय क्या है?

- 'मिशन अंत्योदय' का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के प्रसार के माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है जो लोग गरीबी के कई अभावों से जूझ रहे हैं।
- इस मिशन के तहत ग्राम पंचायत को विक. ास योजना का केंद्र बनाया गया है।
- यह नियोजन प्रक्रिया केरल के लोगों की योजना से प्रेरित है।
- इस मिशन के तहत संविधान की ग्यारह. वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के संबंध में डेटा एकत्र करके ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास अंतरालों का आकलन करने के लिए एक वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है।

पंचायती राज मंत्रालय का विचार स्थानीय स्तर पर बुनियादी जरूरतों में अंतराल की पह. चान करना और इन जरूरतों के वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वैच्छिक संगठनों के संसाधनों को एकीकृत करना है।

मिशन अंत्योदय से संबंधित मुद्दे-

2019-20 के मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण ने पहली बार एकत्र डेटा जिसमें 2.67 लाख ग्राम पंचायतों में ढांचागत अंतराल को उजागर किया गया, जिसमें 1.03 बिलियन आबादी वाले 6.48 लाख गांव शामिल थे।

असाइन किया गया अधिकतम स्कोर मान 100 था, जबकि भारत में कोई भी राज्य 90 से 100 के शीर्ष स्कोर ब्रैकेट में नहीं आता है। 1,484-ग्राम पंचायतें निचले ब्रैकेट में आती हैं। 80 से 90 के स्कोर रेंज में भी 10 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश दिखाई नहीं देते हैं। रिपोर्ट किए गए सभी 18 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों की कुल संख्या केवल 260 है, जो देश की कुल 2,67,466 ग्राम पंचायतों में से केवल 0.10% है।

केरल रैंकिंग में सबसे ऊपर है, लेकिन राज्य की ग्राम पंचायतों का केवल 34.69% हिस्सा

है। यहां तक कि गुजरात, जो इस श्रेणी में केरल की ग्राम पंचायतों के बाद आता है, वह केवल 11.28% है।
समग्र सूचकांक के आंकड़े भी उत्साहजनक नहीं हैं। हालांकि देश में केवल 15-ग्राम पंचायतें 10 अंकों से नीचे की सीमा में आती है। केरल की सभी ग्राम पंचायतें इससे ऊपर हैं और बाकी राज्यों की तुलना में अलग हैं। जबकि पूरे देश में 70-100 ब्रैकेट में केवल 7.37% का समग्र सूचकांक है, गुजरात जो सूची में सबसे ऊपर है, उसकी सीमा में 20.5% है, उसके बाद केरल (19.77%) और कर्नाटक (17.68%) है। गैप रिपोर्ट और समग्र सूचकांक स्पष्ट शब्दों में दिखाते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का निर्माण एक दूर का लक्ष्य है।

आगे की राह-

बढ़ती ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करने की बहुत आवश्यकता है और सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता और पेयजल आपूर्ति को सही करने की भी जरुरत हैं। लेकिन संसाधनों (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदि) को एकजुट करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।
भारत के राजकोषीय संघवाद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेटा का सही इस्तेमाल ना करना भी एक विफलता है।
पंद्रहवां आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना और क्रियान्वयन का संवैधानिक लक्ष्य मजबूत नीति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय संविधान स्थानीय सरकारों को अनुच्छेद 243G और 243W के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और लागू करने का आदेश देता है, इन लक्ष्यों को मिशन अंत्योदय के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय

1 नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार

नेपाल के पास दवाओं, तेल उत्पादों, कारों और कई अन्य वस्तुओं के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भंडार कम है और अगर चीजें नहीं सुधरी तो यह भंडार सात महीने में खत्म हो जाएगा।
केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की है, जो लोगों को वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करेगा और विदेशी भंडार को बढ़ाने में मदद करेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण-

नेपाल ने विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के बाद कारों, सौंदर्य प्रसाधनों और सोने सहित गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी के मध्य तक सात महीनों में 16% से अधिक गिरकर 1.17 ट्रिलियन नेपाली रुपये ($9.59**bn**; £7.36**bn**) हो गया।
नेपाल की विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत पर्यटन, विदेशी श्रमिकों से प्रेषण और विदेशी सहायता है। इसी अवधि में, विदेशों में काम करने वाले लोगों द्वारा नेपाल को भेजी जाने वाली धनराशि में लगभग 5% की गिरावट आई है।
नेपाल में सरकारी कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद के 43% से अधिक हो गया है, क्योंकि महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने और कोरोना महामारी में मदद करने के उद्देश्य से खर्च बढ़ा है। नेपाल में बढ़ते आयात, प्रेषण के प्रवाह में गिरावट और पर्यटन और निर्यात से कम आय के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी गई है।
आम तौर पर, हर साल सैकड़ों हजारों विदेशी पर्यटक नेपाल आते हैं। हालांकि, कोरोनावायरस महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण संख्या में तेजी से गिरावट आई।
महामारी में विदेशी पर्यटकों में काफी गिरावट और हाल के दिनों में प्रेषण में आई कमी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

नेपाल की मौजूदा आर्थिक स्थिति में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका-

- नेपाल में ऊर्जा का मुख्य आपूर्तिकर्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) है।
- नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन (एनओसी) हर महीने आठ और 23 तारीख को दो किस्तों में आईओसी का भुगतान करता है।
- एनओसी महीनों से आर्थिक संकट में है क्योंकि उच्च वैश्विक कीमतों ने कंपनी की बचत को लगभग समाप्त कर दिया है और इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार से संपर्क कर रही है।

नेपाल की चिंताजनक स्थिति-

- विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए, देश को

उन उत्पादों के आयात को नियंत्रित करना होगा जिसमें सबसे अधिक कर राजस्व खर्च होता हैं।

- देश के राजस्व प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत विलासिता की वस्तुएं हैं।
- अगर राजस्व में कमी आती है तो देश में आर्थिक संकट आ जाएगा है।

2 ब्रिटेन की अदालत ने असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी किया

सन्दर्भ-

ब्रिटेन की एक अदालत ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध से संबंधित गुप्त फाइलों के प्रकाशन पर मुकदमे का सामना करने के लिए विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित करने के लिए बुधवार को एक औपचारिक आदेश जारी किया है

असांजे को पिछले महीने उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित करने के कदमों के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, जहां उन्हें आजीवन जेल का सामना करना पड़ सकता है।

खबर की पृष्ठभूमि-

जूलियन असांजे 2010 में सैन्य और राजनयिक फाइलें प्रकाशित करके अमेरिकी जासूसी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

दोषी पाए जाने पर उन्हें 175 साल तक की जेल हो सकती है, हालांकि सटीक सजा का अनुमान लगाना मुश्किल है।

उन्हें स्वीडन में यौन उत्पीड़न के आरोप में जमानत देने के लिए 2019 से दक्षिण-पूर्व लंदन की एक शीर्ष-सुरक्षा जेल में रिमांड पर रखा गया है।

उस मामले को छोड़ दिया गया था, लेकिन उन्हें अमेरिकी प्रत्यर्पण मामले में उड़ान जोखिम (एक व्यक्ति के मुकदमे या जमानत की सुनवाई से पहले देश छोड़ने की संभावना हो) आधार पर जमानत का उल्लंघन करने के लिए समय काटने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया था।

अमेरिका ने ब्रिटिश अधिकारियों से असांजे को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि वह गुप्त राजनयिक केबलों और सैन्य फाइलों की एक टिप्पणी पर मुकदमा चला सकें, जिसे विकीलीक्स ने 2010 में ऑनलाइन प्रकाशित किया था। उन पर जासूसी के 17 आरोप और कंप्यूटर के दुरुपयोग का एक आरोप है।

अब तक क्या हुआ है?

पिछले साल जनवरी में, एक ब्रिटिश जिला अदालत ने अमेरिकी प्रत्यर्पण अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि असांजे के द्वारा कठोर अमेरिकी जेल की परिस्थितियों में खुद को मारने की संभावना थी।

लेकिन अमेरिकी सरकार ने अपील की, आश्वासन दिया कि विकीलीक्स के संस्थापक को उचित देखभाल मिलेगी और उन्हें एकान्त कारावास में नहीं रखा जाएगा। दिसंबर में, यह पाते हुए कि अमेरिकी अधिकारियों के वादे यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे कि असांजे के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, उच्च न्यायालय ने अमेरिका का पक्ष लिया

अमेरिकी जासूसी अधिनियम -

1917 के जासूसी अधिनियम ने राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने, चित्रों को रिकॉर्ड करने या वर्णन की प्रतिलिपि बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, यह विश्वास करने के इरादे या कारण के साथ कि जानकारी का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान पहुचने या किसी भी विदेशी राष्ट्र के लाभ के लिए किया जा सकता है।

इस अधिनियम ने सशस्त्र बलों में भर्ती में बाधा डालने वाले या सैन्य या नौसेना बलों में अवज्ञा या अविश्वास का कारण बनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आपराधिक दंड भी बनाया है

प्रत्यर्पण क्या है?

- प्रत्यर्पण एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें एक क्षेत्राधिकार किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपराध करने के आरोपी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दूसरे के कानून प्रवर्तन को सौंपता है। यह दो न्यायालयों के बीच एक सहकारी कानून प्रवर्तन प्रक्रिया है और उनके बीच की गई व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं के अलावा, प्रत्यर्पण में अनुरोध करने वाले क्षेत्राधिकार के कानूनी प्राधिकरण को प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की हिरासत का भौतिक हस्तांतरण भी शामिल है।
- वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राज्य, दूसरे के अनुरोध पर, अनुरोध करने वाले राज्य के कानूनों द्वारा दंडनीय अपराध के परीक्षण के लिए एक व्यक्ति की वापसी पर प्रभाव डालता है और उसके शरण की स्थिति के बाहर प्रतिबद्ध होता है।

प्रत्यर्पण योग्य व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है, जिन पर मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया जो हिरासत से भाग गए, और अनुपस्थिति में दोषी ठहराए गए।

भारत का प्रत्यर्पण कानून-

- भारत में, भारत से किसी भगोड़े का विदेशी देश में प्रत्यर्पण या इसके विपरीत की स्थिति को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाता है जो कानून के इस क्षेत्र के लिए मौजूदा विधायी आधार है।
- यह अधिनियम प्रत्यर्पण कानून के पहले सिद्धांत को निर्धारित करता है। यह अन्य देशों के साथ भारत द्वारा की गई संधियों/व्यवस्थाओं/सम्मेलनों के प्रत्यर्पण की बाध्यता के आधार पर निर्धारण करता है
- प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 3 के तहत, भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जा सकती है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित देशों तक विस्तारित किया जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्पण के कानून की व्यापक समझ के लिए, किसी को विशिष्ट संधियों के साथ संयोजन के रूप में प्रत्यर्पण अधिनियम को पढ़ना होगा।

पर्यावरण

1 ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट

समाचार में क्यों

ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत स्थानीय ग्रामीण समुदाय की भागीदारी से प्रत्येक गांव के लिए डेवलप ग्रासलैंड एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। परियोजना को परिणामोन्मुखी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

मूल बातें

- भारत सरकार ने इस परियोजना को खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के सहयोग से शुरू किया है।
- इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसमें शामिल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं।
- यह एक सात साल लंबी परियोजना है जो 2018 में शुरू हुई थी।
- यह पांच राज्यों के उच्च-संरक्षण-मूल्य परिदृश्य में चलाया जा रही है।

1. मध्य प्रदेश- चंबल परिदृश्य
2. मिजोरम- दम्पा परिदृश्य
3. ओडिशा- सिमिलीपाल परिदृश्य
4. राजस्थान- डेजर्ट नेशनल पार्क परिदृश्य
5. उत्तराखंड- कॉर्बेट-राजाजी परिदृश्य

- परियोजना जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना चाहती है।

भारत में पर्यावरण पर कृषि क्षेत्र के नकारात्मक प्रभाव

(आवासों के नुकसान और अति-शोषण के कारण भारत में कृषि जैव विविधता का नुकसान बढ़ रहा है।

(भारत में कृषि क्षेत्र प्रमुख रूप से भूमि और जल उपयोगकर्ता है। फसल अवशेषों को हटाने या जलाने, कम खाद, गहन फसल, उर्वरकों और कीटनाशकों के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आई है। व्यापक सिंचाई योजनाओं के परिणामस्वरूप भूजल और सतही जल संसाधनों दोनों की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट आ रही है।

(कृषि का विस्तार और गहनता प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जंगली प्रजातियों पर दबाव बना रही है।

(संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर कृषि पद्धतियां भी संरक्षित क्षेत्रों और उनके बीच संपर्क के लिए एक खतरा हैं।

(कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि क्षेत्र द्वारा उत्सर्जित मुख्य ग्रीनहाउस गैसें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसका मुख्यालय रोम में है।
- यह 194 देशों और यूरोपीय संघ सहित 195 सदस्यों से बना है।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)

- इसकी स्थापना 1992 के रियो अर्थ समिट की पूर्व संध्या पर की गई थी।
- अपने रणनीतिक निवेश के माध्यम से, **GEF** ग्रह के सबसे बड़े पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए भागीदारों के साथ काम करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों सहित 18 एजेंसियों की एक अनूठी साझेदारी है।
- यह 5 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए एक वित्तीय तंत्र है।

1. मर्करी पर मिनामाटा सम्मेलन
2. स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम सम्मेलन
3. जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीबीडी)
4. मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी)
5. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)।

डेजर्ट नेशनल पार्क

(यह उत्तर-पश्चिमी भारत में थार रेगिस्तान में स्थित है।

(अरावली की पहाड़ियाँ इस मरुस्थल की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती हैं जबकि पश्चिमी सीमा को सिंधु के मैदानी इलाकों द्वारा परिभाषित किया गया है।

(ग्रेट रन आफ कच्छ दक्षिण में सीमा बनाता है जबकि इसकी उत्तरी सीमा उप-हिमालयी मैदानों द्वारा बनाई गई है।

(डेजर्ट नेशनल पार्क के शुष्क क्षेत्र के एक बड़े हिस्से की वनस्पति कांटेदार वन प्रकार के अंतर्गत आती है।

(यह विश्व स्तर पर संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और अन्य स्थानिक जीवों और वनस्प. तियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है।

2 चेरी ब्लॉसम (Cherry Blossom)

हाल ही में भारत में सकुरा जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, कि नई प्रजाति खोजी गई है। यह नई प्रजाति भारतीय राज्य मणिपुर में पाई गई है। **Cherry Blossom** अथवा **Sakura** जापान का राष्ट्रीय पुष्प (**National flower**) है।
भारत के मणिपुर में इसकी नई प्रजाति की खोज के साथ ही भारत **Sakura Map** में शामिल होने वाला 28वां देश बन गया है। इसका मतलब है कि भारत सहित 28 देशों में यह फूल पाया जाता है।

मणिपुर में खोजे गए चेरी ब्लॉसम के इस नए प्रजाति का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर **Dr Dinabandhu Sahoo** के नाम पर रखा गया है। इसका नाम **Prunus Dinabandhuana** रखा गया है।

2016 में डॉक्टर साहू ने ही भारत के पहले **cherry blossom festival** का आयोजन शिला. ंग में कराने की योजना बनाई थी। डॉक्टर साहू अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय छात्र थे।
जापान जैसे देशों में चेरी ब्लॉसम बसंत में दिखाई देते हैं। जापानी चेरी ब्लॉसम वृक्ष का वैज्ञानिक नाम 'प्रून्स येदोएंसिस' (**Prunus ye-doensis**) है जिसे सामान्यत: 'सोमी योशिमा' (**Somei Yoshima**) के नाम से जाना जाना जाता है।
उत्तर-पूर्वी भारत मुख्यत: शिलांग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम 'प्रून्स सेरासोइ. ड्स' (**Prunus cerasoides**) है। इसे 'जंगली हिमालयी चेरी ब्लॉसम इन ऑटम' (Wild Himalayan Cherry and blossoms in autumn) के नाम से भी जाना जाता है।

इसके फल खाने योग्य होते हैं परन्तु ब्लॉसम के मौसम में ये पेड़ हल्के गुलाबी और सफेद रंग के फूलों से भर जाते हैं।
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जिसे जापान में सकुरा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, हर साल अप्रैल में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देश त्योहार मनाते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने में मदद करता है। प्रोफेसर साहू ने कहा कि अकेले वाशिंगटन डीसी, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दुनिया भर से हर साल पर्यटकों से लगभग 126 मिलियन डॉलर कमाता है।

विज्ञान एवं तकनीक

1 इलेक्ट्रिक स्कूटर

शहरी वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों को बदलने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जलवायु के प्रति संवेदनशील और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में उभरे हैं। वह पारंपरिक या जीवाश्म-ईंधन आधारित परिवहन वाहन है लेकिन यह विकल्प कई परिवारों के लिए घातक साबित हुआ है जिन्होंने इस पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को चुना है। पिछले दो गर्म मार्च-अप्रैल महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के कई मामले सामने आए हैं। ये वाहन ओल्ड इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, प्योर ईवी और जितेंद्र ईवी द्वारा निर्मित किए गए थे।

संभावित कारण:
संबंधित निर्माण कंपनियों ने कहा है कि वे आग लगने के संभावित कारणों की जांच कर रही हैं।
यह अनुमान लगाया जाता है कि आजकल मौसम की स्थिति बेहद गंभीर है, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने का प्रमुख कारण हो सकता है। अत्यधिक तापमान के कारण बैटरी अधिक गर्म हो जाती है जिससे आग लग जाती है।

भविष्य की चिंता
ईवी जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल प्रतिस्थापन की व्यवहार्यता, और अन्य लिथियम-आयन बैटरी स्थापित इलेक्ट्रिक उत्पाद जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और सौर ऊर्जा बैकअप स्टोरेज संदेह के दायरे में आ गए हैं।

- इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटना और मरने वालों की संख्या से इलेक्ट्रिक स्कूटर सुरक्षा तंत्र में ग्राहकों का विश्वास कम हो जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एक अन्य संबद्ध चिंता उनकी महंगी कीमतें हैं जो उन्हें कई घरों के लिए वहनीय नहीं बनाती हैं।
- इसका जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) आधारित वाहनों की मुफ्त मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि लोग ईवीएस पर इन वाहनों को पसंद करेंगे जो फिर से शहर के प्रदूषण (शहरी वायु प्रदूषण) को गंभीर बना देगा।

कंपनियों की प्रतिक्रिया प्योर ईवी, ओकिनावा, जितेंद्र ईवी और बूम

मोटर्स जैसी कई इलेक्ट्रिक कंपनियों ने कई स्कूटर बैचों को वापस बुलाने की पहल की है।

- उन्होंने यह भी कहा कि बैटरी पैक पहले से ही अनुपालन करता है और इसका एआईएस 156 के लिए परीक्षण किया गया है।
- एआईएस 156 भारत के लिए नवीनतम प्रस्तावित मानक है। (2010)
- यह मानक मोटर वाहनों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और श्रेणी एल वाहनों (एल-श्रेणी-2W, 3W, क्वाड साइकिल) के रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (आरईईएसएस) के संबंध में सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

सरकार की प्रतिक्रिया

सड़क परिवहन मंत्रालय ने अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र द्वारा इन आग की घटनाओं की जांच का आदेश दिया है और श्री नितिन गडकरी के 'इलेक्ट्रिक निर्माताओं' कंपनियों के खिलाफ कड़े बयान को "उनकी प्रक्रिया में लापरवाही" पाए जाने पर परिणाम भुगतने के लिए बाध्य किया है।

आगे की राह

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग के मामले से गंभीरता से निपटना होगा और अगर भविष्य में ईवी अत्यधिक मौसम के अनुकूल नहीं होंगे तो ईवी अपनाने के उद्देश्य घातक हो जाएंगे और शहरी वायु प्रदूषण और जीएचजी उत्सर्जन की समस्याएं और अधिक गंभीर हो सकती हैं।

2 भारत की हरित हाइड्रोजन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने अपनी हरित हाइड्रोजन नीति जारी की है। जिसमें कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जैसे- अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, बैंकिंग, समयबद्ध मंजूरी के साथ ही भारत के ऊर्जा संक्रमण को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा की गई है ।

भारत के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की प्रासंगिकता-

भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई जबकि अमेरिका के औसत का बारहवां भाग है।

ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव (जैसा कि रूस-यूक्रेन संकट के दौरान देखा गया था), भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। हाइड्रोजन, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हाइड्रोजन, बहुआयामी भूमिका निर्वाहित कर सकता है, जैसे- ऊर्जा भंडारण में, लंबी दूरी के परिवहन में, या औद्योगिक क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में।

यह 2030 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक विस्तारित करने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना का समर्थन करेगा।

भारत के परिवहन क्षेत्र के डीकार्बा. `नाइजेशन में हाइड्रोजन की प्रमुख भूमिका है। औद्योगिक क्षेत्र में- हाइड्रोजन, लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम, तांबा आदि जैसे क्षेत्रों को डी-कार्बोनाइज कर सकता है। इसमें मेथनॉल, सिंथेटिक केरोसिन और ग्रीन अमोनिया जैसे ईंधन के उत्पादन की एक बड़ी संभावना निहित है।

हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा रोड मैप के तीन ई की संकल्पना को पूर्ण करता है, E- ऊर्जा सुरक्षा, E- ऊर्जा स्थिरता और E- ऊर्जा तक पहुंच ।

हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अपनाने में चुनौतियाँ-

2020 में भारत की हाइड्रोजन खपत लगभग 7 मिलियन टन थी। ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई-टेरी) ने अनुमान लगाया है कि 2050 में इसके बढ़कर लगभग 28 मिलियन टन होने की संभावना है। इसलिए हाइड्रोजन के उपयुक्त उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

निरंतर बिजली की बढ़ती मांग के साथ ही, हाइड्रोजन निर्माण की उच्च लागत और पानी की कमी भी एक चुनौती बन सकती है।

इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा 1 किलो हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए लगभग नौ लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

पांच चरणों वाली रणनीति

मांग पक्ष पर पांच-चरणीय रणनीति तैयार की जानी चाहिए।

1) प्रारंभिक मांग उत्पन्न करने के लिए, परिष्कृत उद्योगों जैसे कि रिफाइनिंग और उर्वरकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2) कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन-आधारित उत्पादों जैसे ग्रीन स्टील और ग्रीन सीमेंट का निर्माण करने वाले उद्योगों को सरकारी नीतियों द्वारा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

3) प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन का सम्मिश्रण एक बड़े बूस्टर शॉट के रूप में कार्य कर सकता है। इस अधिशेष सम्मिश्रण को विनियमित करके और एच-सीएनजी स्टेशनों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर सुगम बनाया जा सकता है।

4) साथ ही, एफसीईवी को बढ़ावा देने के लिए, समर्पित गलियारों पर हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों को स्थापित करने की योजना बनाई जा सकती है जहां लंबी दूरी की ट्रकिंग की व्यापक संभावनाएं हो।

5) यूरोपीय देशों की तर्ज पर कार्बन टैरिफ की अवधारणा को पेश करने की आवश्यकता है।

आपूर्ति पक्ष पर एक पांच-चरणीय रणनीति तैयार की जानी चाहिए-

1) इसकी लागत को जीवाश्म ईंधन के बराबर लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश में तेजी लाई जानी चाहिए।

2) सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (सतत) योजना का लक्ष्य 15 एमएमटी कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करना है, जिसे हाइड्रोजन में रूपांतरित कर लाभ उठाया जा सकता है।

3) नवजात प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और स्केल-अप के लिए, हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं के लिए एक व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) और प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

4)उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को लागू करके इलेक्ट्रोलाइजर्स की लागत को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता-

हाइड्रोजन अगले कुछ दशकों में, भारत की ऊर्जा ट्रेजेकटरी को एक ऊर्जा आयातक से एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातक के रूप में रूपांतरित कर, भारत के ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। भारत जापान और दक्षिण कोरिया जैसे भावी ऊर्जा के आयातक देशों को अधिशेष ऊर्जा का निर्यात कर सकता है।

3 भारत में गर्म (वार्म) टीके

चर्चा में क्यों?

भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर (IISc) में इनक्यूबेट की गई कंपनी, बेंगलुरु स्थित मिनवैक्स (Mynvax) प्रयोगशालाओं द्वारा एक 'गर्म(वार्म)'वैक्सीन विकसित की जा रही है।

गर्म (वार्म) टीके क्या हैं?

एक गर्म टीका एक हीट टॉलरेंट टीका है जो रूम टेम्परेचर पर भी अपनी प्रभावशीलता बनाए रख सकती है और इसके लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है।

मिनवैक्स टीको (Mynvax Vaccine) के बारे में-

बेंगलुरु स्थित मिनवैक्स प्रयोगशालाओं द्वारा मिनवैक्स नाम के कोविड- 19 टीका विकसित किया जा रहा। यह वार्म वैक्सीन वर्तमान में मौजूद टीकों में अद्वितीय है क्योंकि इसे चार सप्ताह के लिए 37 डिग्री सेल्सियस और 90 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहीत किया जा सकता है।

बायोस्पेक्ट्रम की एक रिपोर्ट में, डेटा से पता चलता है कि मिनवैक्स के सभी फॉर्मूलेशन का परिणाम एंटीबॉडी में होता है जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा SARS-CoV-2 के सभी प्रकारो के प्रभाव को निष्प्रभावी करने में सक्षम है।

गर्म टीकों के लाभ-

बढ़ा हुआ वितरण:-

- एक वैक्सीन जो गर्म तापमान के प्रति सहनशील है वह भारत के उच्च तापमान, दूर-दराज के दूरदराज के क्षेत्रों और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित क्षमताओं को देखते हुए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। इसकी सततता के कारण यह जनता की पहुंच में भी होगी।
- यह बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है तथा उन स्थितियों में सहयोगी हो सकता है जहाँ सैकड़ों हजारों टीकों की खुराक को कम अवधि के भीतर कई टीकाकरण बिंदुओं पर ले जाने की आवश्यकता होती है।

हेल्थकेयर वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम दबाव-

- भारत की कोल्ड स्टोरेज क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन यह मुख्य रूप से केवल शिशुओं के लिए ताजा भोजन, औषधीय उत्पाद, फूल, रसायन और टीके रखती है।
- परन्तु टीके रखने योग्य कोल्ड-स्टोरेज में से अधिकांश अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं।
- यह वैक्सीन अभियान के सभी पक्षों में सम्मिलित लाखों फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है।

लंबे समय तक प्रभावकारिता

- उच्च तापमान के संपर्क में आने पर टीके आसानी से अपनी प्रभावशीलता खो सकते हैं, यही कारण है कि उन्हें परिवहन के दौरान आकस्मिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के कारण कोल्ड चेन में रुकावट से बचाना चाहिए।

गर्म टीकों (वार्म टीको)से सम्बद्ध मुद्दे-

- इस प्रकार के टीको की आवश्यकता उच्च आय वाले देशों में नहीं है । परन्तु ये देश गर्म टीको को प्राथमिकता नहीं देते परिणामस्वरूप विकासशील और अविकसित देश जिनके पास ऐसे टीकों की वास्तविक आवश्यकता है, वे पीछे रह जाएंगे।
- सामान्य या ठंडे टीकों की तुलना में गर्म टीकों की प्रभावकारिता के बारे में चिंताएं हैं।

आगे की राह -

गर्म टीकों का विकास भारत जैसे विकासशील देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इन टीकों का उपयोग अन्य बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है। भारत जैसे देश में अधिकांश क्षेत्रों में गर्म समशीतोष्ण जलवायु, एक बड़ी ग्रामीण आबादी और भूमि क्षेत्र, पहुंच और प्रभावकारिता से सम्बंधित कई चिंताएं रहती हैं । गर्म टीके (वार्म टीके) भारत में ऐसी समस्याओं के लिए रामबाण के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आर्थिक

1 एटीएम से कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आरबीआई ने देश भर के एटीएम से "कार्डलेस नकद निकासी" की घोषणा की है। इन निकासी को यूपीआई के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है।

इस सिस्टम की क्रियाविधि :-

- कार्डलेस नकद निकासी को यूपीआई के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है।
- एटीएम से यूपीआई का उपयोग करके नकदी निकालने का विकल्प दिखाई देगा ।
- एक बार जब कोई उपयोगकर्ता इस विकल्प को चुन लेता है, तो वे निकासी की जाने वाली राशि को इनपुट कर सकते हैं।
- एटीएम पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। इसके बाद यूजर्स को अपने यूपीआई ऐप के जरिए उस कोड को स्कैन करना होगा और एटीएम से कैश निकालने के लिए पासवर्ड डालना होगा।
- अब तक, यूपीआई के माध्यम से केवल खातों के बीच धन हस्तांतरण सक्षम किया गया था। इस विकल्प के साथ उपभोक्ता बिना कार्ड के एटीएम से नकद निकाल सकते हैं।

एटीएम से कार्डलेस नकद निकासी के लाभ :-

1. सुरक्षा में वृद्धि :-

- आरबीआई गवर्नर के अनुसार, कार्डलेस नकद निकासी से नकद निकासी लेनदेन की सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह कार्ड स्किमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगा।

2. उपयोगकर्ताओं को किसी भी बैंक के एटीएम से नकद लेने में सक्षम करना :-

- वर्तमान में, केवल कुछ बैंकों के मौजूदा ग्राहकों को कार्ड के बिना और विशिष्ट बैंक के एटीएम नेटवर्क से नकदी निकालने की अनुमति है।
- हालांकि, कार्ड रहित निकासी में इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति देने के आरबी. आई के कदम से उपयोगकर्ता किसी भी बैंक के एटीएम से नकदी प्राप्त कर सकेंगे।

3. यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र अधिक प्लेयर्स को आमंत्रित करेगा :-

- भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम से भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में और अधिक प्लेयर्स को आमंत्रित किया जाएगा ताकि ग्राहकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

कार्डलेस नकद निकासी सुविधा की सीमाएं और चुनौतियां :-

1. लेनदेन की सीमा :-

- यह सुविधा बोझिल है और इस सुविधा की कुछ निकासी सीमाएँ हैं तथा इसमें लेन-देन का शुल्क लिया जाता है।
- HDFC बैंक के ग्राहकों को कार्डलेस कैश पद्धति का उपयोग करके प्रतिदिन 10,000 रुपए और प्रति माह 25,000 रुपए तक निक. ालने की अनुमति है। इन निकासी पर प्रति लेनदेन 25 रुपए का सेवा शुल्क भी है।
- फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यूपीआई आधारित नकद निकासी पर समान प्रतिबंध और सेवा शुल्क होगा या नहीं।

2. मापनीयता :-

- इस सुविधा की मापनीयता एक चुनौती हो सकती है क्योंकि यह देखना होगा कि कितने बैंक अपने ग्राहकों के लिए इसे जल्द ही आ. रम्भ करते हैं।

3. मोबाइल बन सकते हैं टारगेट :-

- कार्ड रहित निकासी में, कार्ड की सुरक्षा भेद्यता कम से कम होती है तथा यह सुरक्षा सुभेद्यता जल्द से जल्द मोबाइल-सक्षम सुविधा में स्थानांतरित हो जाएगी।
- इस सुविधा के उपरान्त मोबाइल लेन-देन का केंद्र बनेगा जिससे यह जालसाजों के लिए अगला लक्ष्य बन जाएगा।

डेबिट कार्ड का भविष्य :-

- डेबिट कार्ड जारी करना बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे नकद निकासी के अतिरिक्त कई अन्य सुविधाएं देते हैं।
- उनका उपयोग किसी रेस्तरां, दुकान, या किसी विदेशी देश में भुगतान के लिए किया जा सकता है।
- डेबिट कार्ड एक बहुत विकसित वित्तीय उत्पाद है और अपनी पूर्णता के लिए पहले से ही कई पुनरावृत्तियों से गुजर चुका है।
- इसके आगे के विकास में, हम डेबिट कार्ड के लिए नए उपयोग यथा ईएमआई भुगतान देख सकते हैं।

निष्कर्ष :-

- डेबिट कार्ड के परिष्कृत स्तर पर यूपीआई के आने में अभी भी काफी समय है।

• इसके अलावा, डेबिट कार्ड अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों, जो यूपीआई जैसे शुद्ध डिजिटल भुगतान समाधानों के साथ सहज नहीं हैं या उच्च लेनदेन सीमा चाहते हैं, में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाएगा।

2 आईएमएफ ने भारत के विकास पूर्वानुमान को 8.2% तक घटाया

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष (2022-23) में 8.2% बढ़ने का अनुमान है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 9% के पूर्व की तुलना में काफी धीमी है। वैश्विक विकास 2021 में अनुमानित 6.1 प्रतिशत से 2022 और 2023 में 3.6 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी उपस्तिथि बनाए रखेगा। यद्यपि भारत की वृद्धि धीमी हो रही है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का प्रभाव कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन पर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत जैसे शुद्ध तेल आयातकों को कमजोर घरेलू मांग और कम शुद्ध निर्यात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तेल की ऊंची कीमतों से निजी खपत और निवेश पर असर पड़ने की उम्मीद है।

• यूक्रेन-रूस संघर्ष से आर्थिक क्षति 2022 में वैश्विक विकास में मंदी में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। यूक्रेन के सकल घरेलू उत्पाद में गंभीर दोहरे अंकों की गिरावट और रूस में एक बड़ा संकुचन कमोडिटी बाजारों, व्यापार और वित्तीय चैनल के माध्यम से दुनिया भर में फैलने की संभावना अधिक है। भले ही युद्ध विकास को कम करता है, यह मुद्रास्फीति में इजाफा करेगा। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति कीमतों के दबावों को नियंत्रित करने और विकास को सुरक्षित रखने के बीच ट्रेड-ऑफ को जटिल बनाएगी। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव से केंद्रीय बैंकों की नीति सख्त होने से ब्याज दरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कई देशों के पास अपनी अर्थव्यवस्थ।ाओं पर युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय नीति की गुंजाइश सीमित है। आक्रमण ने आर्थिक विखंडन में योगदान दिया है क्योंकि बड़ी संख्या में देशों ने रूस के साथ वाणिज्यिक संबंध तोड़ दिए हैं और महामारी के बाद की रिकवरी को जोखिम में डाल दिया है। यह नियम-आधारित ढांचे के लिए भी खतरा है जिसने वैश्विक आर्थिक एकीकरण की सुविधा प्रदान की है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। इसके अलावा, यह संघर्ष महामारी से उत्पन्न आर्थिक तनाव को बढ़ावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

• IMF की स्थापना 1944 में 1930 की महामंदी के बाद की गई थी। 44 संस्थापक सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की मांग की। आज, इसकी सदस्यता में 190 देश शामिल हैं, जिसमें 150 देशों के कर्मचारी शामिल हैं।

• इसके संगठनात्मक ढांचे के शीर्ष पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। IMF के दिन-प्रतिदिन के कार्य की देखरेख इसके 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो संपूर्ण सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है और IMF कर्मचारियों द्वारा समर्थित है। प्रबंध निदेशक IMF स्टाफ के प्रमुख और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। उसे चार उप प्रबंध निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

• आईएमएफ के संसाधन मुख्य रूप से उस पैसे से आते हैं जो देश सदस्य बनने पर अपनी पूंजी सदस्यता (कोटा) के रूप में भुगतान करते हैं। आईएमएफ के प्रत्येक सदस्य को विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी सापेक्ष स्थिति के आधार पर एक कोटा सौंपा गया है। वित्तीय कठिनाई में पड़ने पर देश इस पूल से उधार ले सकते हैं।

• आईएमएफ वास्तविक या संभावित भुगतान संतुलन समस्याओं का सामना करने वाले सदस्य देशों को-आपातकालीन ऋण सहित- ऋण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय भंडार के पुनर्निर्माण में मदद करना, उनकी मुद्राओं को स्थिर करना, आयात के लिए भुगतान जारी रखना और अंत. र्निहित समस्याओं को ठीक करते हुए मजबूत आर्थिक विकास की स्थिति को बहाल करना है।

• मुख्यालय- वाशिंगटन डीसी
• रिपोर्ट प्रकाशित

1. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
2. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट
3. फिस्कल मानिटर

NOTES

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गयी

खुशी और जीवन मूल्यांकन पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 10वें संस्करण को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने जारी किया है। विगत 5 वर्षों की तरह फिनलैंड को इस वर्ष भी सूची में शीर्ष स्थान मिला है। इसके बाद क्रमशः डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड का स्थान है। 2022 में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर रहा। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत 149 देशों में से 139वें स्थान पर था। इस वर्ष की सूची में अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया, इसके बाद क्रमशः लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कई कारकों के आधार पर देशों को रैंक करती है जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, आदि।

रैंक	देश
1	फिनलैंड
2	डेनमार्क
3	आइसलैंड
4	स्विट्जरलैंड
5	नीदरलैंड
136	भारत

2. भारतीय सेना सेशल्स रक्षा बलों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिये 2022 संपन्न

भारत तथा सेशेल्स की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिये 22 से 31 मार्च तक सेशेल्स रक्षा अकादमी (एसडीए) में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अर्ध-शहरी वातावरण में शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ विभिन्न अभियानों के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करना है। भारत की तरफ से अभ्यास में 2/3 गोरखा राइफल्स समूह के सैनिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। बता दें कि लैमिटिये शब्द का अर्थ दोस्ती होता है। भारत तथा सेशेल्स लैमिटिये सैन्य अभ्यास का आयोजन 2001 से द्विवार्षिक रूप से करते आए हैं। ऐसा पहला आयोजन 2001 में सेशेल्स में आयोजित किया गया था है।

3. केरल चुनिंदा स्थानों पर कार्बन-न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरूवात करेगा

केरल चुनिंदा स्थानों पर कार्बन-न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरूवात करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। इस उद्देश्य के लिए, केरल सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन-न्यूट्रल फार्मिंग लागू की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन-न्यूट्रल फार्म स्थापित किए जाएंगे। अलुवा स्थित राज्य बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

4. अंतरिक्ष उपग्रहों को नष्ट करने के लिए चीन ने एक लेजर हथियार विकसित किया

चीनी शोधकर्ताओं ने षरिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर (आरकेए)ष नामक एक माइक्रोवेव मशीन विकसित की है जो अंतरिक्ष उपग्रहों को जाम या नष्ट करने में सक्षम है। आरकेए में केए-बैंड में 5-मेगावॉट वेव बर्स्ट उत्पन्न करने की क्षमता है। केए-बैंड विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। आरकेए जमीन से लक्ष्य को साध सकता है लेकिन इसे उपग्रहों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है कि आरकेए एक निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) है। बता दें कि निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) दुश्मन के उपकरण और/या कर्मियों को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा के बजाय केंद्रित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

5. स्पोर्टस्टार एसेस अवाड्र्स 2022 घोषित, नीरज चोपड़ा को 'स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया

हाल ही में स्पोर्टस्टार एसेस पुरस्कारों की घोषणा की गयी है। इसी क्रम में एथलीट और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर (ट्रैक एंड फील्ड) का पुरस्कार मिला। उन्हें स्पोर्टस्टार ऑफ द ईयर (पुरुष) पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भ. रोत्तोलक मीराबाई चानू को श्स्पोर्टस्टार ऑफ द ईयर (फीमेल)श का पुरस्कार दिया गया। इनके साथ ही बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन को व्यक्तिगत खेल श्रेणी में श्शस्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर', सविता को टीम स्पोर्ट्स श्रेणी में श्स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयरश और अवनि लेखारा को महिलाओं में श्पैराथलीट ऑफ द ईयरश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं महिला हॉकी टीम को श्ब्रेकथ्रू परफॉरमेंस ऑफ द ईयर' पुरस्कार के लिए चुना गया है।

6. नागालैंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया

नागालैंड विधानसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना को पूरी तरह से लागू किया है। दूसरे शब्दों में नागालैंड विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली राज्य विधानसभा है। परियोजना लागू होने के साथ ही नागालैंड विधान सभा के सदस्य अब सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) विधायी कार्य के संचालन में सदन के अध्यक्ष की मदद करेगा। इसे एनआईसी क्लाउड मेघराज पर तैनात किया गया है।

राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (नेवा) कार्यक्रम :-

श्वन नेशन-वन एप्लीकेशनश की थीम पर विकसित नेवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राज्य विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में विभाजित की गयी है।

7. लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में उपविजेता बने

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चौंपियनशिप के फाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से हार गए। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में विक्टर एक्सेलसन ने लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से हराया। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले वे 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। सबसे पहले 1947 में प्रकाश नाथ इस प्रतिष्ठित चौंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। इसके बाद 1980 में प्रकाश पादुकोण और फिर 2001 में पुलेला गोपीचंद ने इस खिताब को अपने नाम किया था। इसके बाद 2015 में सानिया नेहवाल फाइनल पहुंची थी। बता दें कि लक्ष्य सेन ने हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपरसीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं।

8. तमिलनाडु के वाद्ययंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया

तमिलनाडु के पारंपरिक पवन वाद्ययंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह वाद्ययंत्र कुंभकोणम के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। बता दें कि नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीई टैग प्रदान करने के लिए जनवरी 2014 में आवेदन किया गया था। जिसके आधार पर जीआई रजिस्ट्री द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कलाकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नागस्वरम को परी नागेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम का मुख्य भाग पारंपरिक लकड़ी ष्अचाष या हार्डविकिया बिनाटा से बनाया जाता है। हार्डविकिया बिनाटा एक पेड़ है जिसे इंडियन ब्लैक वुड के नाम से भी जाना जाता है। यंत्र की खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए पुराने घरों के कुछ हिस्सों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यंत्र बेलनाकार होता है और इसकी लंबाई ढाई फीट होती है।

9. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गयी

स्विस स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईक्यूएयर ने हाल ही में अपनी नवीनतम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर था। जबकि ढाका 78.1 पीएम 2.5 स्तर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का वायु प्रदूषण 2021 में और खराब हुआ है। इसका औसत वायु प्रदूषण पीएम 2.5 के स्तर 58.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर था। वैश्विक स्तर पर, दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में चौथे स्थान पर था। दुनिया का सबसे प्रदूषित स्थान राजस्थान का भिवाड़ी है। जबकि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दुनिया के शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से दस भारत में हैं। जबकि 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 भारतीय शहर हैं। रिपोर्ट में दावा किया है कि चेन्नई को छोड़कर सभी छह मेट्रो शहरों में पिछले साल वायु प्रदूषण (पीएम 2.5) के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में बांग्लादेश औसत पीएम2.5 स्तर 76.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था। इससे पहले भी 2018, 2019 और 2020 में बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था। वहीं चाड, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और भारत भी दुनिया के सबसे पांच प्रदूषित देशों में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी देश 2021 में डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता मानक (पीएम 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) को पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ।

10. रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाया

रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। अपने नवीन अनुमान में फिच ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से बढ़ेगी। इसने पहले फिच ने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 10.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों (रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण) और बढ़ती महंगाई ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए फिच ने सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर के अनुमान को 0.6% संशोधित कर 8.7% कर दिया है। फिच ने विश्व जीडीपी के अपने अनुमान को भी 0.7% घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया है। बता दें कि पिछले हफ्ते, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी 2022 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है।

11. भारतीय संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया

प्रोफेसर श्रीपति टुडू ने पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है। ओल चिकी लिपि को ओल सिकी, ओल और संताली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। श्रीपति टुडू पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सिद्धो-कान्हो-बिरशा विश्वविद्यालय में संथाली भाषा के सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने यह पहल संथाली भाषा जानने वाले लोगों के लिए संविधान को और अधिक पहुंच योग्य बनाने के लिए शुरू की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, पूरे भारत में लगभग 70 लाख लोग संथाली बोलते हैं। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और वे मुख्य रूप से बंगाल, झारखंड, ओडिशा, असम आदि में रहते हैं। संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। कोलकाता के एक प्रकाशक टॉरियन पब्लिकेशन ने ओल चिकी लिपि में संविधान का अनुवाद प्रकाशित किया है।

(CONSTITUTION)
(PREAMBLE)

12. कान्स फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा होंगी दीपिका पादुकोण

- भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 2022 कान्स फिल्म फेस्टिवल जूरी का हिस्सा होंगी।
- जूरी में पांच पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं।
- फ्रांस के अभिनेता विंसेंट लिंडन कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण में जूरी का नेतृत्व करेंगे।
- जूरी इस साल के विजेताओं की घोषणा 28 मई को करेगी।

कान फिल्म समारोह के बारे में :-

o इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 को हुई थी।
o यह कान्स, फ्रांस में हर साल आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है।
o यह दुनिया भर के वृत्तचित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों को प्रदर्शित करता है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई बिलियड्र्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। यह उनका आठवां एशियाई बिलियड्र्स खिताब है। इस वर्ष एशियाई बिलियड्र्स चैंपियनशिप का आयोजन कतर दोहा में आयोजित किया गया था।

- 2022 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है। जबकि उन्हें ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में भारत के कारोबारी गौतम अदानी को 12 स्थान प्राप्त हुआ है।

- हाल ही में कुवैत में 53.2 डिग्री सेल्सियस (127.7 डिग्री फारेनहाइट) का तापमान दर्ज किया गया, जिससे यह दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक बन गया।

- सर्दार बर्डीमुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वह अपने पिता गुरबांगुली बर्डीमुखमेदोव का स्थान लेंगे।

- भारतीय अर्थशास्त्री जयती घोष बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के 12 सदस्यी उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य बनीं। बता दें कि वह आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की भी सदस्य हैं।

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हैदराबाद में 24 से 27 मार्च 2022 तक श्विंग्स इंडिया 2022श का आयोजन किया। इस आयोजन का विषय "इंडिया/75: एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज" था।

- मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को श्स्पोर्ट्स आइकनश पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें क्रिकेटर सनथ जयसूर्या, जमैका के धावक असफा पॉवेल आदि सहित 16 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित किया गया था।

- अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पी. सुलिवन ने 2022 के लिए एबेल पुरस्कार जीता है। सुलिवन को टोपोलॉजी और इसके बीजीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। टोपोलॉजी गणित की एक शाखा है। यह सतहों के गुणों से संबंधित है जो विकृत होने पर नहीं बदलते हैं। टोपोलॉजिकल रूप से, एक वृत्त और एक वर्ग समान होते हैं।

- ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरूमध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। वह श्रीलंका के तलाईमन्नार से तैरकर तमिलनाडु के धनुष्कोडी तक आईं।

- भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन द्वारा भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच पुणे के लुल्लानगर में अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया गया है।

- भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास ‘दस्तलिक’ के तीसरे संस्करण में भाग लिया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन यांगियारिक (उज्बेकिस्तान) में किया था।

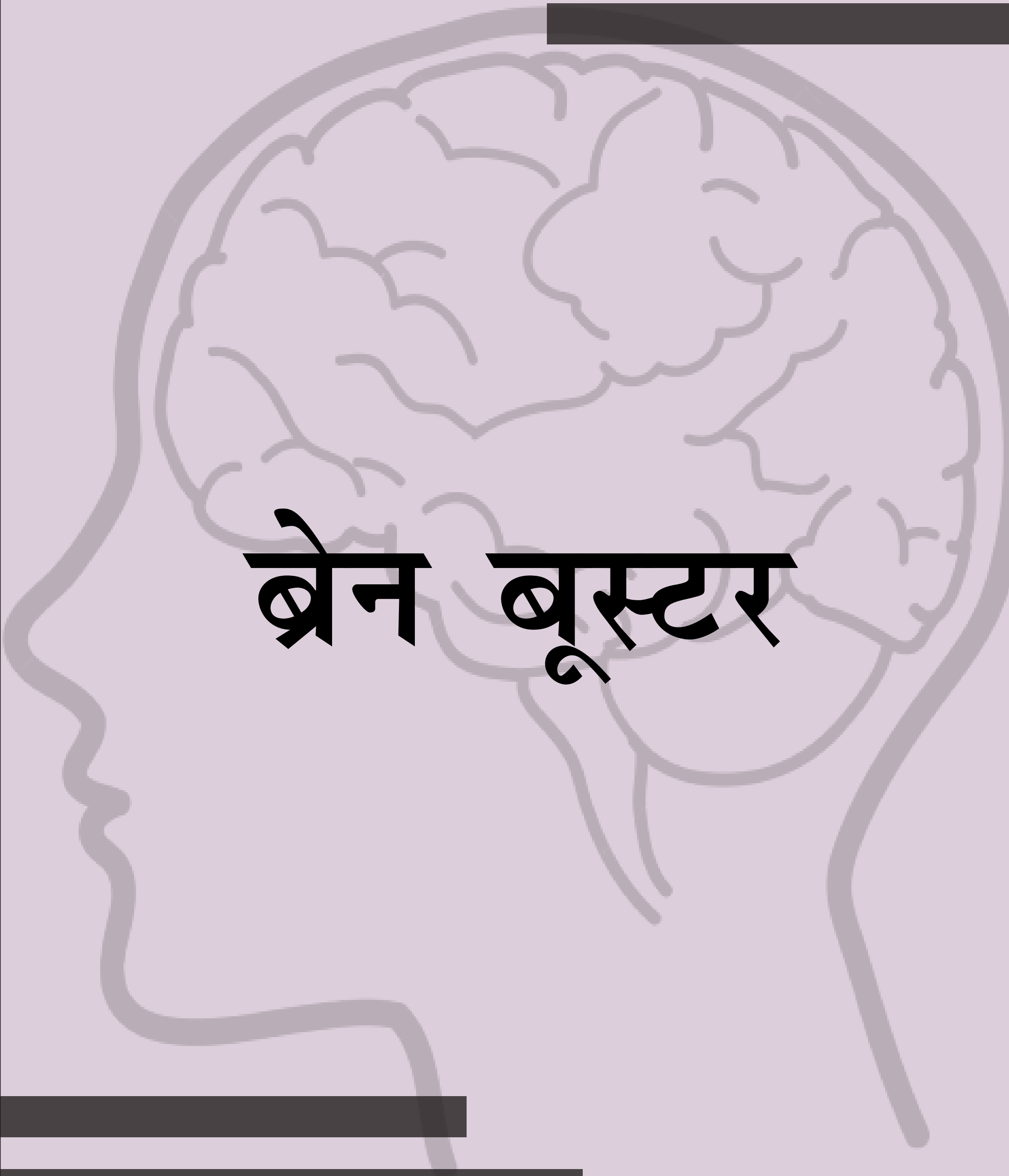

ब्रेन बूस्टर

प्रवर्तन निदेशालय

1. खबरों में क्यों

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित हेरफेर की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली और गुड़गांव में तलाशी ली।

2. प्रवर्तन निदेशालय के बारे में

- प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच ऐजेंसी है, जो निम्नलिखित विधियों को प्रवर्तित करता है
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999(फेमा)– विदेशी विनिमय नियंत्रण विधियों एवं विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने के साथ-साथ उन आरोपियों पर, जिनके विरूद्ध निर्णय दिया गया है शास्तियां लगाने के अधिकार के लिए एक सिविल विधि जो अर्द्ध न्यायिक अधिकार से युक्त है।
- धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002(पीएमएलए)– अपराधिक गतिविधियों से व्युत्पन्न की गई परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए जॉंच करने और उस संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त करने/कुर्क करने एवं धन शोधन में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए अधिकारियों को अधिकार देने वाली एक आपराधिक विधि।

3. धन शोधन

- अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त, तस्करी और अन्य संगठित अपराध, जिसमें नशीले पदार्थों की बिक्री और बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति भी शामिल है, के माध्यम से काफी मात्रा में धन पैदा किया जाता है।
- इस प्रकार पैदा किए गए धन को 'दागदार' और दूषित धन/काला धन कहते हैं।
- धन शोधन अपराधों में संलिप्त होकर धन कमाने की प्रक्रिया है, जिसमें दूषित धन/काले धन को वैध बनाने की कोशिश की जाती है।

4. ईडी का शक्ति स्रोत

- पीएमएलए को भारत के बाहर धन की पार्किंग को रोकने और धन की विभिन्न परतों का पता लगाने के लिए लाया गया था।
- ईडी को अधिनियम की धारा 48 और 49 के तहत जांच करने का अधिकार मिला है।
- विदेशों में धन शोधन के मामले में, पीएमएलए अदालत को अनुरोध पत्र भेजने का अधिकार है।
- उक्त सरकार तब एजेंसी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों को साझा कर सकती है।

5. ईडी द्वारा हस्तक्षेप

- जब भी किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा कोई अपराध दर्ज किया जाता है, जिसने ₹1 करोड़ से अधिक की अपराध की आय अर्जित की है, ईडी कार्रवाई करता है।
- ईडी धन शोधन का संदेह होने पर तलाशी (संपत्ति) और जब्ती (धन/दस्तावेज) भी कर सकता है।

6. प्रशासन द्वारा पीएमएलए का प्रयोग

- वित्त मंत्रलय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध के मामलों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है।
- वित्तीय आसूचना इकाई – भारत द्धएफआ. ईयू-इंडियाऋ, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रलय के अधीन केन्द्रीय राष्ट्रीय अभिकरण, प्रवर्तन अभिकरणों और विदेशी वित्तीय आसूचना ईकाइयों के संबंधा में संदिग्धा वित्तीय का. रोबारों से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रक्रिया चलाने, विश्लेषण करने और उसके फैलाव के बारे में जांच के लिए उत्तरदायी है।

7. धन-शोधन के खिलाफ सयुंक्त राष्ट्र प्रस्ताव

एंटी-धन शोधन/ आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।

- आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन (1999)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (2000) और
- भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (2003)

8. ईडी की भूमिकाएं और कार्य

- ईडी पीएमएलए की धारा 16 (सर्वेक्षण की शक्ति) और धारा 17 (खोज और जब्ती) के तहत, यह तय करने के बाद कि धन को लूटा गया है, तलाशी (संपत्ति) और जब्ती (धन / दस्तावेज) करता है। उसके आधार पर, अधिकारी तय करेंगे कि धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं।
- धारा 50 (समन, दस्तावेज पेश करने और सबूत देने आदि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियां) के तहत, ईडी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाए बिना सीधे तलाशी और जब्ती भी कर सकता है।
- यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ईडी को अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर करने के लिए 60 दिन का समय मिल. ता है क्योंकि पीएमएलए के तहत सजा सात साल से अधिक नहीं होती है।

चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौता

1. खबरों में क्यों

चीन की सरकार ने 19 अप्रैल को कहा कि उसने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों विदेश मंत्रियों, वांग यी और यिर्मयाह मानेले द्वारा हस्ताक्षरित समझौता, चीन के लिए प्रशांत द्वीप राष्ट्र में सुरक्षा बलों को तैनात करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

2. सोलोमन द्वीप समूह के बारे में

- सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में जातीय रूप से मेलनेशियन द्वीपों के समूह का हिस्सा है और पापुआ न्यू गिनी और वानुअतु के बीच स्थित है।
- द्वीपों पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण था।
- सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ, ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक संवैधानिक राजतंत्र बनने के लिए द्वीप 1978 में स्वतंत्र हुए।
- सोलोमन द्वीप द्वारा अपने घरेलू जनजातीय संघर्षों को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ घनिष्ठ सुरक्षा संबंध स्थापित हुए।

3. सुरक्षा समझौते के बारे में

- अंतिम समझौते को सार्वजनिक नहीं किया गया है, हालांकि इसे लीक हुए मसौदे की तर्ज पर माना जाता है
- दस्तावेज के अनुसार ष्सोलोमन द्वीप समूह, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, चीन से पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन और सशस्त्र बलों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करने के लिए सोलोमन द्वीप भेजने का अनुरोध कर सकता है। मानवीय सहायता प्रदान करना, आपदा नियंत्रण करना, या पार्टियों द्वारा सहमत अन्य कार्यों पर सहायता प्रदान करना मुख्य कार्य होंगे।"
- इसमें कहा गया है कि "चीन अपनी जरूरतों के अनुसार और सोलोमन द्वीप समूह की सहमति से, जहाजों को भेजना, लॉजिस्टिक पुनःपूर्ति करना, सोलोमन द्वीप समूह में रुकना तथा संक्रमण कर सकता है।"
- समझौते में यह भी शामिल है,

a) चीनी सुरक्षा परिनियोजन के लिए अनु. रोध कैसे भेजे जा सकते हैं,

b) किसी तीसरे पक्ष को व्यवस्था को सार्वजनिक करने से किसी भी पक्ष को रोकने के लिए गोपनीयता, और

c) समझौते की अवधि, जो पांच साल तक चलेगी और जिसे बढ़ाया जा सकता है।

4. अन्य देशों से प्रतिक्रिया

- ऑस्ट्रेलिया की सोलोमन द्वीप समूह से निकटता को देखते हुए, चिंता एवं निराशा व्यक्त की है।" इस समझौते को पारदर्शिता की कमी के साथ विकसित किया गया है तथा यह हमारे क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर करने की क्षमता रखता है।
- व्हाइट हाउस समझौते के संभावित क्षेत्रीय सुरक्षा निहितार्थ, एक वास्तविक स्थायी सैन्य उपस्थिति की स्थापना, शक्ति-प्रक्षेपण क्षमताओं तथा एक सैन्य स्थापना के बारे में चिंतित है।

5. सोलोमन द्वीप में चीन की दिलचस्पी के कारण

- प्रशांत द्वीप समूह दुनिया के उन कुछ क्षेत्रों में से हैं जहां चीन की राजनैतिक मान्यता के लिए ताइवान से प्रतिस्पर्धा है।
- कोई भी देश जिसे चीन के साथ आधिका. रिक रूप से संबंध स्थापित करने हैं, उसे ता. इवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने होंगे।
- सोलोमन द्वीप, छह प्रशांत द्वीप राष्ट्रों में से एक था, जिसके ताइवान के साथ आधि कारिक द्विपक्षीय संबंध थे।
- 2019 में, सोलोमन द्वीप समूह ने कि. रिबाती के साथ चीन के प्रति अपनी निष्ठा बदल ली।
- छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में महाशक्तियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए संभावित वोट बैंक के रूप में कार्य करते हैं।
- इन द्वीपीय राष्ट्रों में उनके छोटे आकार की तुलना में असमान रूप से बड़े समुद्री विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (खनिज और अन्य संसाधनों में समृद्ध) हैं।
- यही कारण है कि इन 'छोटे द्वीपीय राष्ट्रों' को 'बड़ा महासागरीय राष्ट्र' भी कहा जाता है।
- सोलोमन द्वीपसमूह में मत्स्य पालन के साथ-साथ लकड़ी, खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण भंडार है।
- वे रणनीतिक रूप से चीन के लिए प्रशांत द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों के बीच खुद को सम्मिलित करने के लिए स्थित हैं।
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए ।न्ञै के उदय को देखते हुए, वर्तमान परिदृश्य में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

1. खबरों में क्यों?

राज्य द्वारा संचालित ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) पर एक बडा साइबर हमला हुआ, जिसमे कंपनी के कुछ सर्वरों में सेंध लगी थी । रैंसमवेयर हमले में कंपनी का असम में स्थित मुख्यालय चपेट में आया था।

2. साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता

- अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र भारत में सभी रैंसमवेयर हमलों का सबसे अधिक लक्षित राज्य था। उसे 42% हमलों का सामना करना पड़ रहा था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हैकर समूहों के लिए अधिक आर्थिक रूप से लाभदायक क्षेत्रों में से एक है। ये हैकर भारतीय फर्मों से आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके फिरौती का भुगतान करने के लिए कहते हैं।
- 2021 में चार भारतीय संगठनों में से एक को रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा। भारतीय संगठनों में रैंसमवेयर में 218% की वृद्धि देखी गई - जो वैश्विक औसत 21% से अधिक है।

3. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के बारे में

डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) द्वारा संकल्पित, 22 पेज की रिपोर्ट भारत के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद, लचीली और जीवंत साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए 21 क्षेत्रों पर केंद्रित है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं :-

- सार्वजनिक सेवाओं का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण: सभी डिजिटलीकरण पहलों में डिजाइन के शुरुआती चरणों में सुरक्षा पर ध्यान देने और मूल उपकरणों के मूल्यांकन, प्रमाणन और रेटिंग के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है।
- आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा: इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसीटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूत निगरानी होनी चाहिए। उत्पाद परीक्षण और प्रमाणन को बढ़ाने की जरूरत है, और देश की अर्धचालक डिजाइन क्षमताओं का विश्व स्तर पर लाभ उठाया जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण: पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (ैबक्।) सुरक्षा को उद्यम सुरक्षा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान: लेनदेन करने वाली संस्थाओं, भुगतान, इंटरफेस और डेटा एक्सचेंज, उपयोग किये जा रहे उपकरणों और प्लेटफॉर्म की मैपिंग और मॉडलिंग, अनुसंधान और खुफिया जानकारी को साझा करना चाहिए।
- राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा: राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा नीतियों और सुरक्षा संरचना, संचालन और शासन के लिए दिशा-निर्देशों को विकसित करने की आवश्यकता है।

4. डीएससीआई रिपोर्ट के सुझाव

- बजटीय प्रावधान: वार्षिक बजट का न्यूनतम 0.25% आवंटन, जिसे 1% तक बढ़ाया जा सकता है, को साइबर सुरक्षा के लिए अलग रखने की सिफारिश की गई है।
- अनुसंधान, नवाचार, कौशल-निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास: रिपोर्ट में आईसीटी के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण में निवेश करने, परिणाम-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिए एक लघु और दीर्घकालिक एजेंडा स्थापित करने और डीप-टेक साइबर सुरक्षा नवाचार में निवेश प्रदान करने का सुझाव दिया गया है।
- एक राष्ट्रीय ढांचा: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और आईएसईए (सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता) जैसे संस्थानों के सहयोग से सुरक्षा में वैश्विक पेशेवर प्रमाणन प्रदान करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
- संकट प्रबंधन: संकट से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी के लिए, क्वैब्ट साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने की सिफारिश करता है जिसमें वास्तविक जीवन के परिदृश्य और उनके प्रभाव शामिल हैं।
- साइबर बीमा: डीएससीआई महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए साइबर बीमा उत्पादों को विकसित करने और उनसे जुड़े जोखिमों की मात्रा निर्धारित करने की सिफारिश करता है।
- साइबर कूटनीति: सरकार को साइबर सुरक्षा में एक जिम्मेदार देश के रूप में ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए और प्रमुख देशों/क्षेत्रों के लिए श्साइबर दूतश भी नियुक्त करने चाहिए।
- साइबर-अपराध जांच: रिपोर्ट में आईटी अधिनियम की धारा 79ए के तहत डिजिटल साक्ष्य से संबंधित राय प्रदान करने वाले केंद्रों को बढ़ाकर, साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना और साइबर अपराधों के बैकलॉग को दूर करने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पांच साल का रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की गई है।

5. आगे की राह

केंद्र ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2021 का मसौदा तैयार किया है जो समग्र रूप से राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि साइबर आतंकवाद पर वैश्विक कानूनी ढांचा विकसित करने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय करने की उसकी अभी कोई योजना नहीं है।

कुरील द्वीप समूह

1. खबरों में क्यों

रूस के पूर्वी सैन्य जिले ने मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में कुरील द्वीपों पर 3,000 से अधिक सैनिकों और सैन्य उपकरणों के साथ सैन्य अभ्यास करने के बारे में दुनिया को सूचित किया। जापान ने 22 अप्रैल, 2022 को कुरील द्वीप समूह (उत्तरी क्षेत्रों) को रूस का ष्अवैध कब्जाष् बताया ।

2. कुरील द्वीप समूह का स्थान

- ये चार द्वीपों का एक समूह है जो ओखोटस्क सागर तथा जापान के सबसे उत्तरी प्रान्त, होक्काइडो के उत्तर में, उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
- मास्को और टोक्यो दोनों द्विपों पर संप्रभुता का दावा करते हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से द्वीप रूसी नियंत्रण में हैं।
- टोक्यो का दावा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से विवादित द्वीप जापान का हिस्सा रहे हैं।

3. द्वीपों का महत्व

- दक्षिण कुरील अपनी अवस्थिति के कारण रूस के लिए सामरिक महत्व के हैं।
- कुनाशीर और इटुरुप के बीच जलडमरूमध्य सर्दियों में जमता नहीं है।
- द्वीपों का नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि व्लादिवोस्तोक में स्थित रूसी प्रशांत बेड़े के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रशांत महासागर तक साल भर पहुंच उपलब्ध रहे।

4. विवाद का कारण

- जापान निम्न संधियों द्वारा द्वीपों पर संप्रभुता का दावा करता है
  - (शिमोडा संधि, 1855,
  - (संेट पीटर्सबर्ग की संधि, 1875
  - (पोर्ट्समाउथ संधि, 1905
- रूस निम्न संधियों द्वारा द्वीपों पर संप्रभुता का दावा करता है
  - (याल्टा समझौता, 1945
  - (पॉट्सडैम घोषणा, 1945
  - (सैन फ्रांसिस्को संधि, 1951
- रूस के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को संधि के अनुच्छेद 2 के तहत, जापान ने ष्कुरील द्वीप समूह के सभी अधिकार, स्वामित्व और दावे को त्याग दिया था।"
- जापान का तर्क है कि सैन फ्रांसिस्को संधि का उपयोग यहां नहीं किया जा सकता क्योंकि सोवियत संघ ने कभी शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए।
- जापान और रूस तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध में हैं क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

- 1956 में, जापानी प्रधान मंत्री इचिरो हातोयामा की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद चार में से दो द्वीप जापान को वापस कर दिए जाएंगे।
- लगातार मतभेदों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं होने दिए हैं।
- 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव की जापान यात्रा के दौरान ही सोवियत संघ ने माना कि द्वीप एक क्षेत्रीय विवाद का विषय हैं।

5. समाधान के प्रयास

- 1991 के बाद से, विवाद को सुलझाने और शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के कई प्रयास हुए हैं।
- सबसे हालिया प्रयास प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व में था, जब विवादित द्वीपों के संयुक्त आर्थिक विकास की योजना थी ।
- वास्तव में, दोनों देश 1956 के जापान-सो. वियत संयुक्त घोषणा के आधार पर द्विपक्षीय वार्ता करने पर सहमत हुए थे।

- रूस के साथ संबंध सुधारने के जापान के प्रयास, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता से प्रेरित थे और रूस अपने उर्जा खरीदारों में विविधता लाने और विदेशी निवेश लाने की आवश्यकता से प्रेरित था।

6. आगे क्या

- 22 अप्रैल का बयान दोनों देशों के बीच संबंधों को और नुकसान पहुंचाएगा।
- जापान को रूस-चीन गठबंधन का डर है क्योंकि जापान के चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद तथा एक असहज इतिहास है।
- जापान इसे रूस को और अलग-थलग करने और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के ष्आद. तन अपराधीष् के रूप में चित्रित करने के एक अवसर के रूप में देख सकता है।
- टोक्यो को यह लग सकता है कि यूक्रेन पर आक्रमण यह साबित करता है कि कुरील द्वीप समूह को वापस पाना अब असंभव है।
- कुरील द्वीप समूह पर जापान की नीति में बदलाव से रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कड़वाहट ही आएगी।
- यह जापान के खिलाफ दो पड़ोसियों, चीन और रूस के एक साथ आने की संभावना को आगे बढ़ाएगा।

भारत की कोयला दुविधा

1. खबरों में क्यों

रॉयटर्स के अनुसार, भारत ने अपने राज्यों से अगले 3 वर्षों के लिए कोयले का आयात बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि इन्वेंट्री का निर्माण किया जा सके और मांग को पूरा किया जा सके।

2. वर्तमान स्थिति

- अप्रैल में, भारत में 100 से अधिक ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक महत्वपूर्ण लेवल (आवश्यक स्टॉक के 25% से कम) से नीचे गिर गया, जबकि पूरे भारत में 50 से अधिक संयंत्रों में यह 10% से कम था।
- ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले कोयले का भंडार, पिछले नौ वर्षों में, सबसे न्यूनतम स्तर पर है। बिजली की मांग लगभग चार दशकों में सबसे तेजी से बढ़ रही है।

3. कोयला संकट के बारे में

- कोयला और खान मंत्री, प्रह्लाद जोशी के अनुसार, देश की ऊर्जा जरूरतों का 55% कोयला से पूरा किया जाता है।
- भारत ऊर्जा आउटलुक 2021 की रिपोर्ट भारत में ऊर्जा का उपयोग 2000 के बाद से दोगुना हो गया है, 80% मांग अभी भी कोयले, तेल और ठोस बायोमास द्वारा पूरी की जा रही है।
- देश ने पिछले अक्टूबर में भी ऐसी ही स्थिति का अनुभव किया था, लेकिन कोयले के भंडार की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक है क्योंकि गर्मी के कारण बिजली की मांग अधिक होगी।
- शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ेगी।
- IEA का अनुमान है कि COVID-19 से बाधा के बावजूद, भारत की मांग 2040 तक लगभग 5% प्रतिवर्ष बढ़ने की उम्मीद है।

4. खपत पैटर्न के बारे में

- कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कोयला आधारित संयंत्रों की पूंजी लागत जल विद्युत और परमाणु संयंत्रों की तुलना में कम होती है, इसलिए यह देश में ऊर्जा सुरक्षा का सबसे व्यवहार्य संबल बनाता है।
- परंपरागत संसाधनों की क्षमता वृद्धि को बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से और मदद मिली है।
- हाल ही में वाशिंगटन में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के कोयला उपयोग कम करने के प्रयासों में यूक्रेन युद्ध से बाधा उत्पन्न होगी।

5. अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भारत का रुख

- 2029-30 के लिए उत्पादन क्षमता मिश्रण पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट का अनुमान है कि सकल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा उस वित्तीय वर्ष तक लगभग 40% होने की उम्मीद है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी तक देश में कुल 152.90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
- इसमें सौर ऊर्जा से 50.78 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 40.13 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10.63 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.84 गीगावाट और बड़ी जल विद्युत से 46.52 गीगावाट शामिल हैं।
- प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500GW बिजली क्षमता स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

6. चुनौतियां

- संयंत्र की क्षमता जरूरी नहीं कि वह ग्रिड के लिए पैदा की गई वास्तविक शक्ति में तब्दील हो, इसका कुछ हिस्सा गर्मी या ट्रांसमिशन नुकसान जैसे बाहरी कारकों के कारण क्षय हो जाता है।
- यह नवीकरणीय और पारंपरिक दोनों स्रोतों पर लागू होता है।
- सौर और पवन ऊर्जा परिवर्तनशील संसाधन हैं जिनमें श्परिवर्तनशीलताश विशेष रूप से चरम मांग की अवधि के दौरान उजागर होती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से एक संतुलनकारी कार्य की आवश्यकता होगी।

7. ट्रांसमिशन और स्टोरेज के बारे में

- पारेषण और भंडारण परिवर्तनशीलता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए केंद्रीय हैं। ख वे भारत में उपभोक्ताओं के बीच श्डक कर्वश बिजली की मांग से निपटने में मदद करते हैं।
- बत्तख के समान, वक्र एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है जो दिन के दौरान ऊर्जा की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है।
- पवन और सौर दोनों के परिवर्तनशील स्रोत होने के कारण - एक पूरक मॉडल स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है।

गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने की भारत की इच्छा

1. खबरों में क्यों

यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। भारत उन देशों को गेहूं निर्यात करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत से गेहूं आयात के लिए अनुरोध किया है । विश्व व्यापार संगठन के नियम राष्ट्रों के स्वामित्व वाले स्टॉक से गेहूं निर्यात करने की भारत की योजना में बाधा साबित हो सकते हैं।

2. भारत के गेहूं स्टॉक की स्थिति

- भारत को चालू वर्ष में 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होने की उम्मीद है।
- सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 24-26 मिलियन टन की आवश्यकता होती है।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में गेहूं का निर्यात 7.85 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वर्ष के 2.1 मिलियन टन से चौगुना था।
- इस वित्त वर्ष में 3 अरब डॉलर मूल्य के लगभग 10 मिलियन टन निर्यात होने की उम्मीद है।

3. भारत के लिए अपेक्षित नए बाजार

- मिस्र और जॉर्डन के अलावा, पूर्वी अफ्रीका के देशों द्वारा भी भारत से आयात करने की संभावना है।
- भारत ने 20 से अधिक देशों को डोजियर भेजे हैं और इन सभी देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है।
- इन देशों में से प्रत्येक द्वारा कीट जोखिम विश्लेषण पर शीघ्र समाधान तक पहुंचना उद्देश्य है ताकि निर्यात को गति मिल सके।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और कृषि मंत्रालय भी बाजार के मुद्दों, यदि कोई हो, को हल करने के लिए कई देशों में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं।

4. निर्यात की सुविधा के लिए उठाए गए कदम

- वाणिज्य मंत्रालय ने गेहूं के निर्यात की सुविधा के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित किया है और शिपमेंट की सुविधा के लिए संबंधित स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी अनुप्रयोगों के लिए कागजी कार्रवाई तैयार की है।
- गेहूं फुल वेसल लोड में जा रहा है और इसे उत्पादन क्षेत्रों से बंदरगाहों तक ले जाने की आवश्यकता है।
- रेलवे गेहूँ ले जाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेक उपलब्ध करा रहा है।

5. खरीदार देशों द्वारा भारतीय गेहूं को मंजूरी देने के मानदंड

- जिन देशों ने पहले भारत से गेहूं का आयात नहीं किया है, वे बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए कीट जोखिम विश्लेषण को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं।
- अन्य विभिन्न मानक भी हैं जिन्हें खरीदार अपने विक्रेताओं के साथ साझा कर रहे हैं।
- वर्तमान में, भारतीय आपूर्तिकर्ता इन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम हैं, भारतीय अधिकारी किसी भी ‘अनुचित’ मानकों को निर्धारित करने के लिए कदम उठाने और समाधान पर बातचीत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

6. विश्व व्यापार संगठन का प्रावधान

- यदि अनाज किसानों से निश्चित कीमतों (भारत के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदे गए हैं तो विश्व व्यापार संगठन के नियम किसी देश के लिए सरकारी स्टॉक से अनाज का निर्यात करना मुश्किल बनाते हैं।
- इस प्रतिबंध के कारण भारत के प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल और दालों को उनकी पूरी क्षमता से निर्यात नहीं किया जा सका है।
- भारत से गेहूं का निर्यात, कृषि निर्यात पर विकासशील देशों का विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ टकराव की एक श्रृंखला में केवल नवीनतम टकराव है।

7. भविष्य का दृष्टिकोण

- सरकार न केवल गेहूं के लिए, बल्कि बाजरा और सुपर फूड सहित सभी अनाज के लिए दीर्घकालिक निर्यात अवसरों के बारे में आशावादी है।
- व्यापार सूत्रों का कहना है कि अगर भारतीय गेहूं की कीमतें प्रतिस्पर्धी बनी रहती हैं और भू-राजनीतिक और मौसम की स्थिति अनुकूल रहती है, तो गेहूं के निर्यात की गुंजाइश अच्छी है।
- भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बाजारों का विश्वास जीता है।
- इसे नए बाजारों में भी खुद को स्थापित करने की जरूरत है और सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए।

निजीकृत हवाई अड्डों में राजस्व बंटवारा

1. खबरों में क्यों

अप्रैल, 2022 में तमिलनाडु सरकार ने एक नीति नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि हवाई अड्डे के निजीकरण या संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के मामले में राज्य सरकार को केंद्र से मुआवजे का दावा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने नीति का समर्थन किया।

2. हवाई अड्डों का निजीकरण

- वर्ष 2003 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डे के उन्नयन के प्रस्ताव के साथ भारत में हवाई अड्डों के निजीकरण की शुरुआत हुई ।
- मनमोहन सिंह सरकार ने भी कुछ हवाई अड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे लागू नहीं कर सकी।
- 2019 में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल के तहत लीज पर दिया गया ।
- 2021 में, केंद्र ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत पांच वर्षों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित 25 हवाई अड्डों को और मुद्रीकृत करने की योजना बनाई है।
- तमिलनाडु के 4 हवाईअड्डे चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) योजना का भाग हैं।

3. तमिलनाडु का प्रस्ताव

- एनएमपी के तहत, केंद्र ने तमिलनाडु में निजीकरण के लिए चार हवाई अड्डों को चिन्हित किया है।
- केंद्र ने राज्य से चेन्नई हवाई अड्डे के लिए 64.57 एकड़ पट्टा भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है।
- तमिलनाडु सरकार ने 19 अप्रैल को विधानसभा में एक नीति नोट पेश किया।
- नोट में कहा गया है कि एएआई हवाई अड्डों के निजीकरण की नीति पर सक्रियता से काम कर रहा है।

- इसलिए, यदि राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है और एएआई को मुफ्त में हस्तांतरित करती है और फिर भूमि किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दी जाती है।
- उस मामले में प्राप्त मूल्य/उपार्जित राजस्व, राज्य सरकार के साथ आनुपातिक रूप से साझा किया जाना चाहिए, जो राज्य सरकार द्वारा भूमि में किए जा रहे भारी निवेश को दर्शाता है।

- भूमि का मूल्य, उचित स्तर पर, हवाई अड्डे के स्पेशल पर्पस व्हीकल में राज्य सरकार की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना चाहिए या हवाई अड्डे को किसी निजी पार्टी को स्थानांतरित करने से पहले एक उचित राजस्व बंटवारे की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. छत्तीसगढ़ और झारखंड के दृष्टिकोण

- छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जब केंद्र और राज्य एक कमाई की परियोजना के लिए एक साथ आते हैं, तो सरकार की पूंजी भूमि के मामले में एक शेयरधारक के रूप में मौजूद होती है।
- जब वह परियोजना किसी तीसरी इकाई को बेची जाती है जो कि एक निजी पार्टी है, तो कंपनी की संपत्ति, जिसमें बुनियादी ढांचे के अलावा, भूमि भी शामिल है। इसलिए राज्य सरकार को जमीन का मूल्य दिया जाना चाहिए।

- संयुक्त उद्यम में केंद्र से निवेश बुनियादी ढांचे के रूप में होता है जबकि राज्य सरकार के लिए यह भूमि के रूप में होता है।
- इसलिए, ऐसे प्रत्येक उद्यम में, भूमि का मूल्य राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए यदि इसे किसी तीसरे पक्ष को बेचा जाता है जो एक निजी संस्था है।
- झारखंड सरकार ने "भूमि राज्य की है" कहकर प्रस्ताव का समर्थन किया है। लेकिन अगर केंद्र इसे निजी पार्टियों को सौंप रहा है, तो राजस्व को राज्य सरकार के साथ साझा किया जाना चाहिए।

5. केंद्र का रुख

- नागर विमानन मंत्रालय ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।
- समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मामले को लेकर फैसला सरकार के उच्च स्तर पर लिया जाएगा।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न

Q1. केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विश्व में एक मात्र तैरता हुआ उद्यान है, जो मणिपुर में स्थित है व लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है।
2. इस राष्ट्रीय पार्क में ब्रो-ऐन्टलर्ड हिरण या संगाई पाये जाते है।
3. पार्क के स्थायी प्रवाह/फ्लडिंग के कारण पार्क को खतरा रहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से से सही है।

(a) केवल 1 **(b)** केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 **(d)** 1, 2 और 3

Q2. निम्नलिखित में से कौनसे ई-कचरे हैं?

1. ब्रोमीनेटेड फ़्लेम रिटार्डेंट्स
2. बेरियम
3. बेरिलियम
4. हैग्जावेलेंट क्रोमियम
5. क्लोरोफ्लोरोकार्बन
6. जिंक
7. कैडमियम

नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2, 3, 4, 6 और 7
(b) केवल 1, 2, 3, 4 और 7
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

Q3. एक खाद्य श्रृंखला

(a) एक प्रजाति की जनसंख्या के अन्तर्गत पायी जाती है।
(b) यह प्रत्येक जीव की संख्या है, जो दूसरों द्वारा भक्षण किये जाते हैं।
(c) जिस क्रम में जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे पर निर्भर रहती है यह उसे प्रदर्शित करती है।
(d) इनमें से कोई नहीं।

Q4. 'आर्द्रभूमि के महत्व' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं।

1. आर्द्रभूमि स्थलीय और जलीय परिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र होते हैं।
2. वे जलस्तर उच्च और सापेक्षता: स्थिर रखते है।
3. वे बाढ़ कम करते हैं, और संलग्न पोषक एवं ठोस तत्वों को बाँधे रखते हैं।
4. वन्यजीवों के भोजन एवं प्रजनन के किए आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं।

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।

(a) केवल 1 **(b)** केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3 **(d)** 1, 2, 3 और 4

Q5. यूनेस्को के जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में अगस्त्यमाला जैव आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अगस्त्यमाला जैव आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट में स्थित है।
2. यह कृषिजन्य पौधों के अद्वितीय आनुवांशिक भण्डार हैं।
3. यह तीन राज्यों राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं-

(a) केवल 1 **(b)** केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 **(d)** 1, 2 और 3

Q6. भारत और अमेरिका ने फुल ब्राइट-कलाम जलवायु फेलोशिप का शुभारंभ किया है। इस संदर्भ में नीचे दिये गये कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए:

1. फुलब्राइट-कलाम जलवायु फेलोशिप केवल डाक्टरेट पश्चात् अनुसंधान के लिए पेश की गयी है।
2. यह फेलोशिप कार्यक्रम भारतीय अनुसंधानवेत्ताओं को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अमेरिकी संस्थानों के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनायेगा।
3. यह फेलोशिप बाई-नेशनल (द्विपक्षीय) यू.एस.-इण्डिया एजुकेशनल फाउंडेशन (यूएसआईईएफ) द्वारा संचालित की जाएगी।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1 **(b)** केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 **(d)** 1, 2 और 3

Q7. ग्रीन-एकाउण्टिंग है-

(a) लेखा का एक प्रकार जो संचालन की पर्यावरणीय लागतों को वित्तीय परिणामों में रूपांतरित करता है।
(b) कार्बन क्रेडिट से आर्थिक लाभ का मापक।
(c) लेखा का एक प्रकार जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पर्यावरणी लाभ को मापने का प्रयास करता है।
(d) उपर्युक्त सभी।

Q8. क्रांतिक पारिस्थितिकी भागदारी कोष (CEPF) है:

(a) एक वैश्विक कार्यक्रम जो गंभीर पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा

के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के अन्य भागीदारों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(b) विकासशील देशों में गंभीर पारिस्थितिकी अवसंरचनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, पेरिस जलवायु समझौते के तहत गठित एक वैश्विक भागीदारी कोष।

(c) स्वतंत्र रूप से संचालित एक वित्तीय संगठन जो सरकारों को जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।

(d) उपर्युक्त में से सभी।

Q9. मेदिनी पुरस्कार प्रदान किया जाता है:

(a) स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा इस्तेमाल करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को।

(b) जैवविविधता संरक्षण से सम्बंधित लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय तथा विदेशी लेखकों को।

(c) प्रत्येक वर्ष वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए।

(d) पर्यावरण तथा उससे संबंधित मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किये गये कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों को।

Q10. 'फूड वेब (खाद्य जाल)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. खाद्य जाल किसी समुदाय की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मध्य अन्त:क्रियाओं तथा अन्तर्सम्बंधों को दर्शाता है।
2. खाद्य जाल का एक दूसरा नाम उपभोक्ता-संसाधन प्रणाली भी है।
3. खाद्य जाल पोषण स्तरों तथा स्थितियों को शामिल नहीं करता।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q11. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन

1. पौधों तथा पशुओं की एक विशाल विविधता को प्रदर्शित करते हैं।
2. वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक संकटमयी पारिस्थितिक प्रणालियों में से एक हैं।
3. ज्यादातर विषुवत् रेखा के आस-पास अवस्थित हैं।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q12. प्रवाल भित्तियाँ हैं-

1. प्रवाल द्वारा स्रावित कैल्सियम कार्बोनेट से बनी पानी के भीतर की एक संरचना।
2. प्राय: 'समुद्र के वर्षा वन' कहे जाते हैं।
3. ये पर्यटन, मत्स्य पालन तथा तटीय रेखा संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
4. ये महाद्वीपीय समुद्र तल के समीप गहरे समुद्र में पाये जाते हैं।

उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

Q13. किसी दिये गये क्षेत्र के प्रजाति संघटन में धीरे-धीरे और स्पष्टत: दृश्य (जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके) बदलाव को कहा जाता है:

(a) पारिस्थितिकी नीश
(b) पारिस्थितिकी उत्तराधिकार
(c) पारिस्थितिकी संतुलन
(d) पारिस्थितिकी परिवर्तन

Q14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैवआवर्द्धन पोषण स्तरों में स्तर दर स्तर विषैले पदार्थों के संकेंद्रण में वृद्धि को दर्शाता है।
2. जैवसंकेंद्रण किसी विशेष जीव के ऊतकों में विषैले रसायनों के संकेंद्रण को दर्शाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Q15. 'बर्ड लाइफ इंटरनेशनल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आईपीसीसी के बाद संरक्षण संगठनों की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भागीदारी है।
2. यह संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवास तथा वैश्विक जैवविविधता के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है।
3. 'बर्ड लाइफ इंटरनेशनल' आईयूसीएन के लिए पक्षियों की लाल सूची का आधिकारिक प्राधिकरण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q16. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड दर्शाता है-

1. अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विशेषीकृत आर्द्रभूमि
2. रामसर अभिसमय के अधीन आर्द्रभूमि
3. तात्कालिक संकट से जूझ रहीं आर्द्रभूमि

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q17. 'बायोकार्बन फण्ड इनीशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लेण्ड--स्केप्स' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित होता है।
2. यह हरित गैस उत्सर्जन में कमी का प्रयास करता है।
3. यह भारत सरकार तथा अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित द्विपक्षीय कोष है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

Q18. 'जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ऐसे क्षेत्र जो उच्च प्रजाति संवृद्धि और साथ ही उच्च प्रजाति स्थानिकता को प्रदर्शित करते हैं, जैवविविधता के हॉटस्पॉट्स कहलाते हैं।
2. जैवविविधता हॉस्टपॉट्स जैवविविधता के महत्वपूर्ण भण्डार वाले ऐसे जैवभौगोलिक क्षेत्र हैं जो मानवीय खतरों से मुक्त होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Q19. निम्नलिखित में कौन-सा भारत में रामसर क्षेत्र अपने अवस्थिति से सही सुमेलित नहीं है?

(a) कंजलि आर्द्रभूमि - पंजाब
(b) रुद्रसागर झील - त्रिपुरा
(c) होकरसर आर्द्रभूमि - जम्मू व कश्मीर
(d) दिपोर बिल - पश्चिम बंगाल

Q20. 'कार्टिजिना प्रोटोकॉल' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) कार्टिजिना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है।
(b) यह जैविक विविधता पर अभिसमय के पूरक के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
(c) कार्टिजिना प्रोटोकॉल 'लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म' को परिभाषित करने के बारे में मौन है।
(d) यह जैविक विविधता को आनुवांशिक रूपान्तरित जीवों से होने वाले सम्भावित खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम हैं।

Q21. निम्नलिखित पर विचार कीजिए -

1. बॉटिनिकल गार्डन
2. जैवमण्डल रिजर्व
3. वन्यजीव सफारी पार्क
4. वन्यजीव अभ्यारण्य
5. पवित्र उपवन
6. जीन बैंक
7. वन्यजीव गलियारे

उपर्युक्त में से कौन से एक्स-सीटु संरक्षण के उदाहरण हैं ?

(a) केवल 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 4 और 5
(c) केवल 1, 3, 6 और 7
(d) केवल 1, 3, 5, 6 और 7

Q22. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्य हैं-

1. वन क्षेत्र की गुणवत्ता बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार
2. कृषि वानिकी तथा सामाजिक वानिकी
3. झीलों का पुनर्नवीकरण
4. वन आश्रित समुदाय की आजीविका में सुधार

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ब्लू-बेबी सिंड्रोम एक न्यूरोलोजिकल सिंड्रोम है, जो पारा विषाक्तता के कारण होता है।
2. मिनीमाटा रोग तब शुरू होता है जब एक शिशु के द्वारा पानी में नाइट्रेट की बड़ी मात्रा का सेवन किया जाता है।

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q24. हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदूषण क्षमता के आधार पर चार रंग योजना पर उद्योगों को पुनर्वर्गीकृत किया है निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ 'व्हाइट केटेगरी इण्डस्ट्रीज' की है/हैं?

1. इनमें 6 उद्योग क्षेत्र शामिल है जो व्यावहारिक रूप से प्रदूषण कर रहे हैं।

2. उद्योगों की इस श्रेणी को संचालित करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q25. 'कार्बन सिंक' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

(a) 'कार्बन सिंक' वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड को खींच-कर इकट्ठा करने की प्राकृतिक प्रणाली है।
(b) मुख्य प्राकृतिक कार्बन सिंक पौधे, सागर और मिट्टी हैं।
(c) उपर्युक्त दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं

Q26. 'कार्बन क्रेडिट' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वित्तीय साधन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक टन को प्रदर्शित करता है।
2. कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन में कमी की गतिविधियों के क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं।
3. कार्बन क्रेडिट्स विकसित देशों की औद्योगिक गतिविधियों को हतोत्साहित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q27. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) कार्बन टैक्स वह कर है जो ईंधन की कार्बन सामग्री पर वसूल किया जाता है।
(b) भारत कार्बन टैक्स की अवधारणा का सार्वभौमिक तौर पर समर्थन करता है।
(c) कार्बन टैक्स, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की एक मजबूत लागत प्रभावी साधन को प्रस्तुत करता है।
(d) कोई नहीं

Q28. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. पद 'परिस्थितिकी तंत्र' सर आर्थर टेन्सले द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया।
2. पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल की एक स्व- विनियमन एवं आत्मनिर्भर संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q29. साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है-

(a) केरल
(b) तमिलनाडु
(c) कर्नाटक
(d) आंध्र प्रदेश

Q30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बायोगैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ की जैविक विखण्डन द्वारा उत्पादित होती है।
2. बायोगैस जीव-जनित पदार्थ से उत्पन्न होती है एवं जैव ईंधन का एक प्रकार है।
3. भारत में बायोगैस का उत्पादन लघु स्तर पर डायजेशन फैसि-लिटीज में खाद के अवायवीय डायजेशन के द्वारा होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर

1.	(d)	20.	(c)
2.	(a)	21.	(c)
3.	(c)	22.	(d)
4.	(d)	23.	(d)
5.	(b)	24.	(b)
6.	(c)	25.	(c)
7.	(a)	26.	(b)
8.	(a)	27.	(b)
9.	(d)	28.	(c)
10.	(b)	29.	(a)
11.	(d)	30.	(c)
12.	(c)		
13.	(b)		
14.	(c)		
15.	(c)		
16.	(d)		
17.	(b)		
18.	(a)		
19.	(d)		

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q1. यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है?
(a) नीदरलैंड
(b) डेनमार्क
(c) स्विट्जरलैंड
(d) आइसलैंड
उत्तर :- **c**

Q2. लैमिटिये किन दो देशों के मध्य आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक सैन्याभ्यास है ?
(a) भारत- मालदीव
(b) भारत- सेशेल्स
(c) भारत- मॉरिशस
(d) भारत- बांग्लादेश
उत्तर :- **b**

Q3. चीन द्वारा विकसित रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर (आरकेए) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. आरकेए में केए-बैंड में 10-मेगावॉट वेव बर्स्ट उत्पन्न करने की क्षमता है।
2. आरकेए द्वारा जमीन से किसी भी उपग्रह पर निशाना साधा जा सकता है।
3. केए-बैंड विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन/कथनों का चयन करें।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 1 और 3
उत्तर :- **d**

Q4. किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 'स्पोर्टस्टार ऑफ द ईयर (फीमेल)' का पुरस्कार प्रदान किया गया है ?
(a) मीराबाई चानू
(b) मैरी कॉम
(c) सानिया नेहवाल
(d) गीता फोगाट
उत्तर :- **a**

Q5. हाल ही में किस राज्य की विधान सभा ने राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना को पूरी तरह से लागू किया है ?
(a) असम
(b) मध्य प्रदेश
(c) नागालैंड
(d) कर्नाटक
उत्तर :- **c**

Q6. पारंपरिक पवन वाद्ययंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. हाल ही में पवन वाद्ययंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
2. यह वाद्ययंत्र तमिलनाडु के कुंभकोणम के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है।
3. यह वाद्ययंत्र पारंपरिक लकड़ी ‘आचा’ या हार्डविकिया बिनाटा से बनाया जाता है।
दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन/कथनों का चयन करें।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 1, 2 और 3
उत्तर :- **d**

Q7. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्बन-न्यूट्रल खेती के तरीकों की शुरूवात करगा ?
(a) कर्नाटक
(b) केरल
(c) तमिलनाडु
(d) आंध्रप्रदेश
उत्तर :- **b**

Q8. आईक्यूएयर के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर था।
2. वैश्विक स्तर पर, दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में चौथे स्थान पर था।
3. दुनिया का सबसे प्रदूषित स्थान उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है।
दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन/कथनों का चयन करें।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 1, 2 और 3
उत्तर :- c

Q9. रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटा कर कितना किया है?
(a) 8.5
(b) 10.3
(c) 8.4
(d) 7.8
उत्तर :- a

Q10. एबल पुरस्कार के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें :
1. वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार ब्रिटिश नागरिक डेनिस पी. सुलिवन को दिया गया है।
2. एबल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन/कथनों का चयन करें।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2 दोनों
(c) केवल 2
(d) कोई भी नहीं
उत्तर :- d

Q11. ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित महाराष्ट्र की जिया राय ने हाल ही में किस जलडमरूमध्य को पार किया है ?
(a) इंग्लिश चौनल
(b) पाक जलडमरूमध्य
(c) मलक्का स्ट्रेट
(d) सुंडा स्ट्रेट
उत्तर :- b

Q12. यूपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. यूपीआई सीधे बैंक खाते से पैसे निकालता और जमा करता है।
2. यूपीआई में लगाए गए लेनदेन शुल्क पूरी तरह से अलग-अलग बैंकों पर निर्भर हैं।
3. यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर :- d

Q13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पेरिस जलवायु समझौते में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत की नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्त की है।
2. नेट शून्य प्रतिबद्धता पंचामृत रणनीति का हिस्सा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर :- b

Q14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. कोयला आधारित बिजली उत्पादन मार्च 2022 तक भारत की कुल बिजली क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत है।
2. भारत विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:- d

Paper IV केस स्टडी

आप एक जिलाधिकारी हैं और तमिलनाडु के एक दूरस्थ जिले में तैनात हैं। भारत सरकार आपके जिले में एक विशाल-परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है. यह विद्युत ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारिक संरचना विकसित करने में सहायक होगा।

यह स्पष्ट है कि इससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा।

परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए आबादी से दूर, बंजर भूमि का प्रयोग किया गया है. यह उच्च स्तर की ऊर्जा-दक्ष तकनीक पर आधारित है. पर्यावरण पर इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा, जबकि ताप विद्युत संयंत्र से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। विकिरण को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा-उपाय किए गए हैं।

जैसे ही मीडिया ने इस परमाणु संयंत्र की जानकारी सार्वजनिक की, एक लोकप्रिय गैर सरकारी संगठन ने आपके जिले में धरना-प्रदर्शन आरम्भ कर दिया। इसने परमाणु-विकिरण के सम्बन्ध में अफवाह फैला दी, और इस संयंत्र को पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित कर दिया। इसने पूर्व में परमाणु संयंत्रों में हुए विस्फोटों के वीडियों सोशल मीडिया में प्रसारित कर दिए और सरकार से इस योजना को निरस्त करने की मांग आरंभ कर दी। बहुत से लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, और देखते-देखते ये एक आंदोलन में तब्दील हो गया।

इसी बीच खुफिया संस्थाएं सूचित करती है, कि इस गैर सरकारी संगठन ने भारत में विकास-परियोजनाओं को बाधित करने के लिए, विदेशी सरकारें भारी मात्रा में धन हासिल किया है।

(a) इस प्रकरण में अंतनिर्हित नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए।

(b) अब आप क्या कार्यवाही करेंगे।

उत्तर

a : दिए गए मामले के अध्ययन में मैं तमिलनाडु में जिलाधिकारी हूं. मुझे लोगों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना है. इस मामले में वस्तुनिष्ठता, विश्वास, देशभक्ति और धारणीय विकास जैसे मूल्य निहित हैं।

नैतिक मुद्दे :

दिए गए मामले में एक लोकप्रिय गैर-सरकारी संगठन अपने निहित स्वार्थो के लिए, देश के लोकतांत्रिक ढांचे का दुरूपयोग कर रहा है. इसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सुरक्षा-उपायों के बारे में लोगों को भ्रमित करके, जनता और सरकार के मध्य अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है. इस गैर सरकारी संगठन ने जनता को विरोध-प्रदर्शन के लिए भड़का दिया है। जनता स्वयं अपने विकास को रोकने के लिए धरना दे रही है। ये गैर सरकारी संगठन मौलिक अधिकारों (अनु019(1)- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता) एवं विरोध प्रदर्शन के अधिकारों का अपने ही देश के प्रति दुरूपयोग कर रहा है। ये कुछ विकसित देशों की दुष्टता भी दिखता है जो विकासशील देशों को, प्रदुषण एवं भूमंडलीय ऊष्मन रोकने के उनके संघर्ष में न ही आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराते है और न ही वित्तीय सहायता देते हैं, लेकिन इनके विकास को बाधित करने के लिए ऐसे अनैतिक प्रयास अवश्य करते हैं।

वास्तव में इन विकसित देशों को डर लगता है कि भारत, अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रयोग यूरेनियम के संवर्धन एवं परमाणु बम बनाने के लिए कर सकता है।

उत्तर b : मेरी कार्यवाही:

सर्वप्रथम मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, इस गैर सरकारी संगठन के बैंक खातों एवं वित्तीय लेन-देन की जांच कराये। धरना-प्रदर्शन के दौरान व्यापक सुरक्षा-व्यवस्था करूंगा।

तत्पश्चात मैं इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के सहयोग से जनता को उन नवीनतम तकनीकों की जानकारी दूंगा, जिनका प्रयोग करके इस संयंत्र के खतरे को न्यूनतम कर दिया गया है। हम उन्हें पर्यावरण-. संरक्षण एवं विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता समझाएंगे. हम उन्हें विकसित देशों (जैसे-फ्रांस) के बारे में जानकारी देंगे जो 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संयंत्र से करते है।

हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं ताप-विद्युत संयंत्र के तुलनात्मक अध्ययन पर कार्यक्रम प्रसारित कराएंगे। इससे जनता को जीवाश्म ईंधन की तुलना में परमाणु ऊर्जा के लाभों को समझने में सहायता मिलेगी।

इसके पश्चात हम परमाणु ऊर्जा संयत्र में अपनाए गए सुरक्षा उपायों एवं वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की राय पर एक वीडियों बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित कर देगें। इससे जनता अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जाएगी।

हम उन्हें इससे होने वाले विकास एवं रोजगार की संभावनाओं के बारे में भी बताएंगे।

कुछ समय में प्रवर्तन निदेशालय अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगा। इससे जनता, गैर सरकारी संगठन के छुपे उद्देश्य को समझ जाएगी और समस्या पूर्णतय: हल हो जाएगी।

व्यक्ति विशेष : पंडिता रमाबाई

भारतीय इतिहास में 1850 से लेकर 1900 तक का वक्त सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इस समय कई मनीषियों ने तात्कालिक भारत में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी प्रखर आवाज बुलंद की। इस काल से संबंधित ऐसी ही मनीषियों में से एक थीं पंडिता रमाबाई, जिन्हें प्रायः भारत की पहली नारीवादी कहा जाता है।

पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। रमाबाई के बचपन का नाम रमा डोंगरे था। केशव चंद्र सेन ने इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की थी। एक बार महाराष्ट्र में एक भीषण अकाल पड़ा जिसकी वजह से रमा के माता-पिता और छोटी बहन का देहांत हो गया। इसके बाद वह अपने भाई के साथ कोलकाता चली आईं। यहां इनके ज्ञान की ख्याति काफी फैल गई, जिसकी वजह से कोलकाता विश्वविद्यालय ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की।

आगे चलकर पंडिता रमाबाई ने रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हुए एक कायस्थ वकील विपिन बिहारी मेधावी से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद इन्होंने अपना जीवन महिला शिक्षा, बाल विवाह एवं विधवाओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। पंडिता रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की एवं मिशनरी गतिविधियों में शामिल हो गई। इन्होंने तात्कालिक पुरुषवादी एवं ब्राह्मणवादी समाज के परंपराओं एवं मान्यताओं पर तर्कों के साथ आलोचना करना प्रारंभ किया और मf. हलाओं की निम्न स्थिति पर सवाल उठाना शुरू किया।

साल 1882 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए एक कमीशन गठित की जिसमें पंडिता रमाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने महिला शिक्षकों, महिला डाक्टरों और महिला इंजीनियरों की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिटिश सरकार ने इनके सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन्हें 'कैसर-ए-हिंद' की उपाधि से सम्मानित किया। अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान पंडिता रमाबाई ने 'द हाई कास्ट हिंदू विमेन' पुस्तक को लिखा जिसमें उन्होंने एक हिंदू महिला होने के दुष्परिणामों की विस्तार से चर्चा की।

1886 में पंडिता रमाबाई अमेरिका पहुंची। गौरतलब है कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना व्याख्यान दिया तब वहां पर रमाबाई की अगुवाई में कई महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यह सवाल उठाया कि यदि हिंदू धर्म इतना महान ही है तो वहां पर महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के भाषण में महिलाओं की अनदेखी पर भी पंडिता रमाबाई के द्वारा प्रश्न उठाए गए। बता दें कि स्वामी विवेकानंद और पंडिता रमाबाई के बीच कई बिंदुओं पर मतभेद थे। हालांकि दोनों तात्कालिक मुद्दों पर अपने विचारों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। जहां स्वामी विवेकानंद धर्म की तार्किक व्याख्या कर रहे थे, तो वहीं पंडिता रमाबाई महिला अधिकारों की वकालत कर रही थी।

पंडिता रमाबाई के प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिका में 'रमाबाई एसोसिएशन' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत में चल रहे विधवा आश्रम के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना था। बाद में उन्होंने भारत लौटकर विधवाओं हेतु समर्पित 'शारदा सदन' की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को सहारा देने हेतु 'कृपा सदन' नाम के एक महिला आश्रम की स्थापना की। जीवन भर महिला अधिकारों एवं भारत के सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाली इस महान महिला की 5 अप्रैल, 1922 को मृत्यु हो गई।

इनके जीवन के संघर्ष को देखते हुए शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का का नाम रमाबाई मेधावी रखा गया। इसी के साथ यूरोपियन चर्च द्वारा 5 अप्रैल को उनकी याद में फीस्ट डे मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1989 में रमाबाई की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था।

मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख शब्दावलियां

छत्र :- शाही छत्र।

चौधरी :- ग्रामों के मुखियाओं की एक श्रेणी ।

चौल :- रेगिस्तान, मरुभूमि

चुंगी-ए-गल्ला :- अनाज कर।

जागीर :- राज्य द्वारा शाही अधिकारियों को वेतन आदि के बदले प्रदत्त जमीन का टुकड़ा।

जहाँदार - विश्व - स्वामी अर्थात् सुल्तान ।

जमातखाना :- सूफी फकीरों की कुटिया या खनकाह।

जमाद अर्खाना :- अलमारी या पोशाकें रखने की जगह।

जासूस :- जासूस, भेदिया, गुप्तचर

जीतल :- दिल्ली सल्तनत के ताँबे के सिक्के ।

जजिया :- इसके दो अर्थ हैं। प्रथमत: - दिल्ली सल्तनत के कुछ समकालीन स्रोतों के अनुसार,भू-राजस्व या लगान के अतिरिक्त वसूल किए जानेवाले सभी कर जजिया थे। द्वितीयत: शरीयत के नियम के अनुसार, गैर-मुसलमानों या काफिरों से व्यक्ति कर के रूप में वसूल किया जाने वाला वार्षिक कर।

जजिया-ए-ताम्बूल :- पान के पत्तों पर लगने वाला कर।

जाबिता :- राज्य द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष नियम या कानून

जकात: - मुसलमानों के लिए निर्धारित दानराशि । प्रत्येक मुसलमान को, अप्रयुक्त या अनियोजित पूँजी से अर्जित आय समेत कुल आय का ढाई प्रतिशत जकात के रूप में दान करना होता था।

जमींदारी: - निजी स्वामित्ववाली पुश्तैनी या आनुवंशिक जमीन।

जवाबित :- राज्य के कानून।

दरोगा :- स्थानीय कार्यालय का प्रभारी।

दारुल अदल :-कपड़ा व अन्य वस्तुओं का दिल्ली का बाजार, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ न्याय का स्थान।

दारुल मुल्क :- राजधानी

दौलतखाना :- सुल्तान इल्तुतमिश का महल

दवातदार :- शाही दवात रखने वाला।

घम्मार :- जमींदार या भू-स्वामी।

दिरहम खरीदगान :- कम कीमतवाले दास।

दीवान :- केंद्रीय सचिव का कार्यालय।

दीवान-ए-अर्ज :-युद्ध मंत्रालय का कार्यालय

दीवान-ए-इंशा :- मुख्य सचिव का कार्यालय ।

दीवान-ए-रियासत :- व्यापार और वाणिज्य मंत्री का कार्यालय।

दीवान-ए- विजारत :- वजीर का कार्यालय।

दीवान-उल-मुस्तखराज :- कर या राजस्व वसूली का कार्यालय।

दरबार :- शाही दरबार।

नायब-ए-अर्ज :- युद्धमंत्री अथवा सैनिक विभाग का उपमंत्री।

नायब-ए-बर्बेक :-बर्बेक (शाही न्यायालय का प्रभारी अधिकारी) का सहायक।

नोयन :-मंगोल उपाधि या सम्मानजनक संबोधन जिसका अर्थ है प्रमुख या उच्चाधिकारी।

नायब-ए-घिबत :- सुल्तान का संरक्षक जो सुल्तान की अनुपस्थिति में उसका कामकाज देखता था।

नायब-ए-लश्कर :- सेना के लिए सुल्तान का सहायक मंत्री सुल्तान का सैनिक सहायक।

नायब-ए-मामलकत :- राजप्रतिनिधि या समूची सल्तनत के लिए सुल्तान का प्रतिनिधि।

जिल्लुलाह- फिलअर्ज :- ष्धरती पर खुदा या अल्लाह की छायाष कुछ सुल्तानों द्वारा अपनाई गई उपाधि

टंका :- सल्तनत काल का चाँदी का सिक्का।

तहकीमत-ए-मुजद्दिद :- एक नवीन या अभिनव शाही आदेश।

तालुक :- जिला।

तोता :- ढाई मिश्काल का माप।

तूमान :- दस हजार सैनिकों की टुकड़ी।

थाना :- पुलिस थाना ।

दबीर :- सचिव ।

दबीर-ए-मुमालिक :- समूचे राज्य या सल्तनत का प्रभारी मुख्य सचिव।

दादबेक :- न्याय का प्रभारी अधिकारी।

दादबेकी :- न्याय अधिकारियों या दंडाधिकारियों द्वारा वसूल किया गया अर्थदण्ड।

नबत :- पौधा, सब्जी (तरकारी) या जड़ी-बूटी, वनस्पति।

नादिम :- दरबारी अथवा सुल्तान के मनोरंजन के लिए नियुक्त व्यक्ति लेकिन जिसे कोई प्रशासनिक कार्य नहीं दिया जाता था।

दाग :- दाग, घोड़ों के पुट्ठे पर लगाया जाने वाला शाही पहचान चिन्ह।

दलाल-ए- बाजारहा :- बाजार के दलाल।

दरोगा :- स्थानीय कार्यालय का प्रभारी एक छोटा अधिकारी।

नायब-ए-मुल्क :- सल्तनत का राजप्रतिनिधि।

नायब-ए-वकील :- वकील का सहायक अथवा सुल्तान के समक्ष न्यायिक मामलों को रखनेवाला व्यक्ति।
नायब-एवजीर :-उप-वजीर।

नायक :- सेना का उच्चाधिकारी या कोई व्यापारी।

नकीब :-राजमहल एवं राजदरबार प्रबंधक।

नौबत :- सुल्तान और उच्चाधिकारियों के महल के बाहर नौबतखाने पर ढोल बजाना।

नबीसंदास :- लिपिक।

नयाबत या ख्वाजगी :- सहायक और नियंत्रक।

नाजिर :- अधीक्षक, निरीक्षक।

निर्ख-ए-बर-अवर्द :- उत्पादन लागत का सिद्धांत।

नोयन :- मंगोल उपाधि या सम्मानजनक संबोधन जिसका अर्थ है प्रमुख या उच्चाधिकारी।

पायबोस :- पैरों को चूमना

पायक :- अनुचर, सेवक

पटवारी :- गाँव की भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला छोटा कर्मचारी।

प्यादा :- पैदल सैनिक।

फरमान :- शाही आदेश या अध्यादेश।

फरमान देह :- आदेश देने वाले व्यक्ति।

फरमान-सबा :- आदेश देने वाला व्यक्ति।

फर्राशखाना :- गलीचे रखने का कमरा (या जगह)।

फर्सख :- 18,000 फुट दूरी का माप।

ध्येय IAS® most trusted since 2003

DHYEYA IAS® most trusted since 2003

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	×
	English	✓	×

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	**Rs 1530**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	**Rs 810**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

Whatsapp: 9205184003

dhyeyaias.com

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I B**hubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744